हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 12 मार्च, 1997

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 1
वर्ष 1997-98 का बजट पेश करना	(6) 21
	(6) 27

मूल्य : 70 00

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 12 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब क्वैश्चन्ज़ होंगे।

Opening of Veterinary Hospital

***198. Shri Dev Raj Diwan** : Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Veterinary Hospital at village Chitana, district Sonipat; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialised ?

पशुपालन मंत्री (श्री हरमिन्द्र सिंह) :

(क) प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) सरकार द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति देने के पश्चात् ही कार्य शुरू किया जा सकता है।

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे विस्तार से बताने की कृपा करें कि मेरे हल्के के किस-किस गांव में क्या-क्या करने की सोच रहे हैं और क्या-क्या स्कीम वे बना रहे हैं ?

श्री हरमिन्द्र सिंह : स्पीकर सर, वैट्रिनरी होस्पीटल और वैट्रिनरी डिस्पैंसरी का प्रोसीजर यह है कि गांव की जो जमीन इसके लिए एलोकेट की जाती है वह ऐनीमल हस्बैंडरी विभाग के नाम ट्रांसफर की जाए। गांव की पापुलेशन और लाईव स्टॉक के बारे में नार्मज़ यह हैं कि गांव की पापुलेशन दो हज़ार और लाईव स्टॉक एक हज़ार होना चाहिए। जहां तक मकान का ताल्लुक है, 3 कमरे होने चाहिएं जिनमें से दो कमरे 12×15 तथा एक कमरा 12×12 होना चाहिए। जब यह विभाग के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम उसकी सैंकशंब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके गांव में होस्पीटल बनाने की स्कीम है। उसके लिए एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। 4 कनाल वहाँ पर जगह है। अभी वहां पर हम कंसीडर करने जा रहे हैं। वहां पर बिल्डिंग बननी है। नैक्सट फाईनैंशियल ईयर में इसको कम्पलीट कर दिया जाएगा।

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है जहां पर 6-7 हज़ार वोट हैं। मैंने इस बारे में कई बार लिखा भी है। वहां पर वैट्रिनरी होस्पीटल न होने के कारण लोग काफी परेशान हैं। मैं मंत्री महोदय से यह तफसील जानना चाहूंगा कि कितने और होस्पीटल्ज़ पूरे हरियाणा में खोलने की स्कीम है ?

श्री हरमिन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि 8वीं फाईव ईयर प्लान के अन्दर स्टेट में 200 वैट्रिनरी डिस्पैंसरीज़ खुल चुकी हैं। वर्ष 1993-94 में 100 वैट्रिनरी डिस्पैंसरीज़ अपग्रेड की गई हैं और 50 नई खोली गई हैं। वर्ष 1994-95 में भी 100 डिस्पैंसरीज़ अपग्रेड की गई हैं और 50 डिस्पैंसरीज़ नई खोली गई हैं। इसी प्रकार से जहां तक इनके गांव में होस्पीटल खोलने की बात है we will take into consideration.

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए और यह क्राईटेरिया है। मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या शहर और गांव में वैट्रिनरी डिस्पैंसरी या होस्पीटल खोलने के कोई क्राइटेरिया में अन्तर है। शहर में अगर कोई होस्पीटल खोला जाता है तो सरकार या महकमें की जिम्मेदारी है कि उसके लिए जमीन का इन्तजाम करे लेकिन अगर गांव में ऐसी कोई डिस्पैंसरी खोली जाती है, तो उसके लिए जमीन गांव वालों से ली जाती है। शहर के लिए तो जमीन और बिल्डिंग का प्रबन्ध सरकार करती है लेकिन गांवों के लिए जमीन और बिल्डिंग के लिए गांव के लोगों से कहा जाता है, क्या यह गांव के लोगों के साथ भेदभाव नहीं है।

श्री हरमिन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री भागी राम जी ने जो सवाल पूछा है, उसकी बाबत मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस प्रकार का जो रूल या एक्ट बना हुआ है, वह हमारी सरकार ने नहीं बनाया है बल्कि पहले की सरकारों के वक्त से चला आ रहा है और गांव अब भी उसी में कवर होते हैं। गांवों के लिए अब भी यही बात है कि एनीमल हस्बैंडरी विभाग के नाम पहले जमीन ट्रांसफर होगी और बिल्डिंग को कम्पलीट करवाएं तभी उस पर प्राइवेट या सरकारी डिस्पैंसरी खुल सकती है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, क्या यही क्राईटीरिया शहरों पर लागू नहीं होता।

श्री हरमिन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह शहरों पर लागू नहीं होता।

श्री भागी राम : यह शहरों पर लागू क्यों नहीं होता है ?

श्री हरमिन्द्र सिंह : यह सप्लीमैंटरी इस मेन सवाल से एराईज़ नहीं होती इसके लिए सैपरेट सवाल पूछें we will take into consideration on that account.

श्री अध्यक्ष : मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूँगा पिछले 10 सालों में जो इलाके राजनैतिक दृष्टि से उपेक्षित रहे हैं और इनके अलावा जिन इलाकों में ये केन्द्र अभी तक नहीं हैं, चाहे वे कोई भी गांव हों, क्या वहां पर ऐसे केन्द्र बनाकर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे ताकि वहां के लोगों को उनका लाभ हो।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो मामर्ज़ बताएं हैं कि जमीन और बिल्डिंग होनी चाहिए तो वहां पर स्टाफ भेजेंगे। मेरे यहां पर तीन गांव हैं जहां पर लोगों ने आधा एकड़ जमीन देकर दो कमरे बनवा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह इरैलेवैंट प्रश्न है। नैक्सट क्वैश्चन।

Construction of New Roads

***207. Capt. Ajay Singh Yadav** : Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether any earth work has been done on the following roads of Rewari District :

(i) Link road from Maheshwari to Garhi Alawalpur ;

(ii) Link road from Shiv Colony to village Kaluwas ;

(iii) Link road to village Bhagwan near Ramgarh; and
if so, the time by which the avove roads are likely to be completed ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Earth work has been done on roads at Sr. No. (i) & (iii).

(b) The roads at Sr. No. (i) and (iii) will be completed during 1997-98 subject to availability of funds.

The Road at Sr. No. (ii) has not been sanctioned.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इस सड़क को बनते हुए डेढ़ साल हो गया है और वहां पर मिट्टी पड़ चुकी है। लेकिन आज वहां पर हालात यह हो गए हैं कि वहां से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इसमें सरकार का काफी पैसा लग चुका है और वहां से मिट्टी उठाई जा रही है। क्या मंत्री जी जिन दो सड़कों का जिक्र किया गया, उनको जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री धर्मबीर यादव : इस सड़क का एस्टीमेट 27 दिसम्बर 1993 को बना था और पास हुआ था जब कैप्टन अजय सिंह जी मंत्री भी थे। पिछले डेढ़ साल में इस सड़क पर 1 लाख 66 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं और इस पर जो काम रह गया है, वह फंड्ज़ की अवेलेबलिटी पर निर्भर करता है। जैसे ही फंड होगा, हम इस पर काम शुरू करवा देंगे।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में होडल टू खामी एक सड़क 12 फुट चौड़ी है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसको 18 फुट चौड़ी करने की कोई स्कीम है ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, ये इस बारे में परपोज़ल हमें भिजवा दें और जो भी इस बारे में मुनासिब होगा, देख लेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इस पर 1 लाख 66 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं और अब यह बात फंड होने पर निर्भर करती है। अगर वहां से मिट्टी उड़ती रही तो इससे प्रदेश का बहुत नुक्सान होगा। अब ये फंड अवेलेबल होने की बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि फंड होने पर यह काम कर दिया जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह इन सड़कों की मरम्मत करवा सके ? क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इन सड़कों की मरम्मत ये 6 महीने में, 9 महीने में या दो साल में करवा देंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : स्पीकर सर, जब इन सड़कों पर काम शुरू हुआ था, उस समय ये मंत्री थे तब क्यों नहीं ये उनको बनवा सके ? तब ये क्या करते रहे ? (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमने उनमें से कुछ पर मिट्टी वगैरह डलवाने का काम शुरू करवाया था।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने कहा है कि जब ये मंत्री थे तो उस समय ये उन सड़कों के लिए क्या करते रहे ? तब इन्होंने वे क्यों नहीं बनवायीं ? लेकिन ये तो भागते भागते पहली अप्रैल को उनको मंजूर कर गए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है चाहे वे ट्रेजरी बैंचिज के हों या विपक्ष के हों, वे चेयर की अनुमति लिए बगैर न बोलें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनकी बात रिकार्ड नहीं कि जाएगी। (विघ्न)

Opening of a Sub-depot of Haryana Roadways at Julana

***213. Shri Sat Narain Lather** : Will the Minister for Transport be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sub-depot of Haryana Roadways at Julana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Sub-depot is likely to be opened ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पाल गुर्जर) :

(क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त "क" के दृष्टिगत प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर साहब, मुझे माननीय मंत्री महोदय से इतने कठोर जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जुलाना में जुमला मालकान की जमीन है और जींद में केवल दो ही सब-डिपो हैं तो अगर ये जुलाना में सब-डिपो बनाने का विचार करें तो हम इनको वहां वह जमीन दिलवा सकते हैं। क्या मंत्री जी वहां सब-डिपो बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मैं यह शब्द वापस ले लेता हूं। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा ? अगर शर्तें पूरी करता है, तो विचार करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या नारनौल में सरकार ने बस-डिपो बनाने के बारे में विचार किया है ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अंडर कंसीडेशन है और एफ०डी० के पास यह एप्रूवल के लिए केस गया हुआ है। जैसे ही वहां से एप्रूवल आ जाएगी, वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा।

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर सर, जो रोडवेज के बस डिपो शहर की आबादी के अंदर आ गए हैं, क्या उनको वहां से कहीं और शिफ्ट करने का सरकार का कोई इरादा है ? इसके अलावा क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि इनका काम क्या इनको बनाना ही है या फिर इनकी रखवाली करने का काम भी इनका ही है क्योंकि मैं गुड़गांव के रोडवेज़ डिपो के बारे में इनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां के रोडवेज़ बस डिपो के एक बहुत बड़े हिस्से पर एनक्रोचमैन्ट हो गया है ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, माननीय साथी ने जो सवाल किया है उससे तो मुझे लगता है कि ये लोग अपने राज में वहां पर कब्जा करवा गए थे। अब इन्होंने हमारे ध्यान में यह बात ला दी है। अगर इन्होंने नाजायज़ कब्जा करवाया है तो हम जरूर कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री खुर्शीद अहमद : स्पीकर सर, कब्जा तो वहां पर हो गया है लेकिन मंत्री जी उसको क्या कंफर्म करवाएंगे या फिर उसको वैकेट करवाएंगे ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, जिसने यह कब्जा करवाया है, उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उस एनक्रोचमैन्ट को वैकेट कराया जाएगा।

श्री धर्मवीर गाबा : स्पीकर सर, इनकी यह पता ही नहीं है कि वहां कब्जा हुआ है या नहीं। जबकि वहां पर कब्जा हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन इनको पता ही नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं चौधरी धर्मवीर गाबा जी को बताना चाहता हूं कि गुड़गांव बस-स्टैण्ड पर हमें इस किस्म की शिकायत मिली थी। वहां कोई टैम्पोरेरी कंस्ट्रक्शन खड़ा किया था उसको उतरवा दिया है। इस बस स्टैण्ड पर अब अगर एक इंच की भी इन्क्रोचमैंट होगी तो उसको हटवाएंगे। मैं गाबा साहब से भी कहूंगा कि इनके पास यदि इस तरह की कोई जानकारी है, तो हमें दें।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि मुरथल जी०टी०रोड के ऊपर रास्ता छोटा है और वहां सवारियां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं और जो वहां पीछे से गाड़ियां आती हैं, वह वहां रुकती नहीं हैं। सुबह के समय डेली पैसेंजर बेचारे काफी तंग हो जाते हैं। जीप में लटककर पहुंचते हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि कुछ गाड़ियों को वहां रोकने के लिए कहा जाए ताकि वे सवारियां लेकर चली जाएं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आज ही उसके लिए आदेश कर दिए जाएंगे और जो सवारियां वहां रुकती हैं उनको बसें लेकर जाएंगी।

I.T.I., Bahadurgarh

***248. Shri Nafe Singh Rathee** : Will the Minister of State for Industrial Training & Vocational Education be pleased to state the time by which the construction work of the building of I.T.I., Bahadurgarh is likely to be completed ?

औद्योगिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री (श्री रमेश चंद्र कौशिक) : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहादुरगढ़ के भवन का निर्माण कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसमें पढ़ाई का काम कब से शुरू किया जा रहा है। पढ़ाई में कौन कौन से ट्रेड लिए जाएंगे और उन ट्रेडों में कितनी सीटें होंगी ?

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसी सैशन से इसे हम पूरे आई०टी०आई० का दर्जा दे रहे हैं। उसके लिए बिल्डिंग तैयार हो गई है। उस पर 65 लाख रुपया खर्च हुआ है।

श्री नफे सिंह राठी : मैंने पढ़ाई के बारे में जानना चाहा था ?

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : पढ़ाई इसी साल से शुरू करवा रहे हैं। इसमें 132 स्टुडैण्टस हैं इस साल इसे पूरे आई०टी०आई० का दर्जा दे रहे हैं जिसमें 12 ट्रेड शुरू हो जाएंगी।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, हसनपुर आई०टी०आई० के बारे में मैंने मंत्री जी को नोट तैयार करके दिया था मैं जानना चाहता हूं कि उस पर कहां तक कार्यवाही अमल में लाई गई है। उसका सर्वे हुआ है या नहीं ? हम उसके लिए जगह देने को तैयार हैं।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि 15 दिन पहले इनका नोट हमें मिला था उस पर सर्वे करवा रहे हैं। उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें कौन-कौन सी ट्रेड हैं और इसमें कितने इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी ?

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : यह मैं आपको बता दूंगा।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसी सैशन से वहां आई०टी०आई० शुरू करने की बात कही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि समय परिवर्तनशील है और मांग आज इस बात की है कि पहले जो विषय थे, उनका महत्व अब कम हो गया है ये जो 12 विषय इसमें रखे गए हैं, ये उन्हीं में से हैं जो पहले थे इससे बेकारी और बढ़ेगी। आज कल कम्प्यूटर का कोर्स या कोई और कोर्स या कौन से आधुनिक विषय हमें देने जा रहे हैं क्या यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहादुगढ़ में कौन-कौन से ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं, वे हैं इलैक्ट्रोनिक्स, स्टैनोग्राफी, रेडियो और टी०वी०, वैल्डर, टर्नर, मशीननिस्ट, कटाई, कढ़ाई और सिलाई, आर्ट एण्ड क्राफ्ट और स्किन केयर आदि। कंप्यूटर वाले कोर्स पर अगले वर्ष सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बापौली आई०टी०आई० को वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, क्या वे कृपया बतायेंगे कि उसको कब तक शिफ्ट करने की संभावना है ?

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : अध्यक्ष महोदय, बापौली आई०टी०आई० को वापिस बापौली में शिफ्ट करने के लिए इस साल सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मेरे हल्के दादरी में टैन प्लस-टू स्कूल के अलावा कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं। इस बारे में मैंने व्यक्तिगत तौर पर तथा मौखिक रूप से भी मंत्री महोदय से बातचीत की थी, वे कृपया बतायें कि वहां पर भी कोई संस्थान खोलने बारे विचार करेंगे या नहीं।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : आपका यह प्रश्न कल लगा हुआ है। कहो, तो आज जवाब दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर कल ही जवाब देना।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस आई०टी०आई० में कितने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। इस प्रश्न पर प्रकाश डालें।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : आप अलग से प्रश्न पूछें। मैं जवाब दे दूंगा।

Income accrued from Income Tax

***228. Shri Krishan Lal** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total income accrued to the State Government from Income Tax during the years 1995-96 and 1996-97, separately ?

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : वर्ष 1995-96 के दौरान हरियाणा सरकार की आय कर में राज्य के हिस्से के रूप में 139.41 करोड़ रुपये की आय हुई। वर्ष 1996-97 के दौरान 140.13 करोड़ रुपये की राशि प्रत्याशित है जिसके प्रति फरवरी, 1997 तक 118.76 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 21.37 करोड़ रुपये की बकाया राशि 31 मार्च, 1997 तक प्राप्त हो जाएगी।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि साल 1995-96 में और 1996-97 में 118.76 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है और 21.37 करोड़ रुपया बाकी है मेरा क्वैश्चन यह है कि हरियाणा प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी फैक्ट्रीज ऐसी हैं, जिनका मुख्यालय प्रदेश से बाहर है और वे बाहर टैक्स जमा कराती हैं और भारत सरकार ने जो कंसाईनमेंट टैक्स एक प्रतिशत किया था, क्या वह हरियाणा प्रदेश में लागू हो रहा है या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि आने वाले वर्ष 1996-97 में इस टैक्स से कितनी राशि आने की अपेक्षा है और क्या इस में बढ़ौत्तरी की संभावना है ? कृपया इसके आंकड़े बतायें।

श्री चरण दास : स्पीकर सर, यह स्पैसिफिक कूवैश्चन नहीं है। अलग से प्रश्न पूछे लें, मैं डिटेल में जवाब में दूंगा।

Shortage of Drinking Water

***219. Shri Satpal Sangwan :** Will the Minister for Public Health be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the fact that there is an acute shortage of drinking water in Charkhi-Dadri; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to provide adqequate supply of drinking water ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :

(क) इस समय शहर में 110 लीटर के नार्म (Norms) के विरूद्ध विभिन्न बस्तियों में 60 लीटर से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर अनुसार पीने का पानी दिया जा रहा है।

(ख) शहर की जल वितरण योजना की बढ़ौतरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 427 लाख रुपये की योजना पर कार्य चल रहा है।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो पानी दादरी में सप्लाई किया जाता है वह दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी से आता है, दादरी में इसकी टेल है। इसके कारण हमारे यहां जो वाटर टैंक हैं, उसकी पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पानी की समस्या को हल करने के लिए लोहारू कैनाल से नाला बनाया जाए।

श्री जगन नाथ : अगर आवश्यकता हुई तो वहां से भी पानी ला सकते हैं।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में नीमड़ी गांव और नंद गांव में पानी की समस्या है। वहां पर वाटर सप्लाई टैंक का प्रावधान कब तक करने जा रहे हैं?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल तो दोनों गांव ही पानी में डूबे रहे थे। (हंसी) वैसे नीमड़ी गांव में हम इनकी अध्यक्षता में इस कार्य के लिए जल्दी ही फांउडेशन स्टोन रखने वाले हैं तथा नंद गांव में इस बारे जल्दी ही गौर किया जाएगा।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के दादरी में पानी की बहुत समस्या है। इसके अलावा दादरी के अंदर एक खुला नाला है, एक तो उसको ढकवाया जाए और एक उसके फिल्टर का प्रबंध किया जाए। चौधरी साहब, अब तो पानी का मजा दे दो। हमारे हल्के के कामोद गांव में पिछले 5 साल से पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है, जिसको मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। इसका तुरन्त कुछ न कुछ समाधान किया जाए।

श्री जगन नाथ : जैसे कि इन्होंने पूछा है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कामोद गांव में 32 लाख रुपये की स्कीम मंजूर कर दी गई है और 4 लाख रुपये इस काम के लिए अलाट भी कर दिए गए हैं। बाकी जहां तक नाले की बात है, यह हम देखेंगे कि यह बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी संभव होगा, हम करेंगे। पूरे शहर के लिए जितना भी सिस्टम जैसे गलियों का वगैरह वगैरह, वह 4 करोड़ 27 लाख रुपये में ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लगेगा।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे हल्के में वैसे तो सारे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन वहां पर पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कि वह इन्श्योर करे कि जितना पानी वहां के लिए अलॉट किया गया है, वह मिल रहा है या नहीं ?

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि सिरसा, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और रोहतक इन 6 जिलों में ज्यादा खारा पानी है। वहाँ पर डी०डी०पी० के अधीन एक स्कीम है, जिसमें गांवों में प्रतिदिन 25 से 70 लीटर के हिसाब से पानी मिल सकेगा। रोहतक जिले के जिन गांवों में पानी की कमी है, उन में से 20 लीटर तक के 85 गांव हैं, 20 से 30 लीटर तक के 104 गांव हैं, 30 से 40 लीटर तक के 179 गांव हैं और 40 लीटर से ऊपर के 73 गांव हैं। इसी प्रकार से जो 20 लीटर से ऊपर पानी प्रतिदिन दिया जाता है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में तो कोशिश नहीं हो सकती है। इसमें समय तो लगेगा ही।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के अंदर पीने के पानी की समस्या है। वहां पर नगर निगम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रेनीवैल योजना के तहत कोई ऐसी स्कीम सरकार के पास है जिससे पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके ?

10.00 बजे **श्री जगन नाथ** : अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में पर्याप्त एवं साफ सुथरा पानी उपलब्ध कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जहां 50 हज़ार की आबादी है, वहाँ 110 लीटर पानी प्रतिदिन कर दिया जाए। जहां एक लाख की आबादी है वहां पर 135 लीटर पानी कर दिया जाए। जहां दो लाख की आबादी है, वहां 180 लीटर पानी कर दिया जाए। इसके अन्दर फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, रोहतक और करनाल यानी सारा हरियाणा कवर होगा।

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी 130 लीटर से 180 लीटर तक पानी की मात्रा बढ़ाने का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। सोनीपत का क्या होगा जहां पर पीने का पानी है ही नहीं ? जहां पर भी बोर करते हैं, खारा पानी निकलता है और 20 मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वहां पर पीने के पानी का प्रबंध कराएंगे लेकिन अभी तक वहां पर किसी गांव में और शहर में कहीं पर भी पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया गया है। वहां पर कई सालों से बहुत सी वाटर सप्लाई स्कीम्ज़ पैंडिंग पड़ी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन अधूरी पड़ी हुई वाटर सप्लाई स्कीम्ज़ को कब तक कम्पलीट कर दिया जाएगा।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, अगर माननीय सदस्य को पीने के पानी के बारे में कोई दिक्कत है, तो ये हमें जो वाटर सप्लाई स्कीम्ज़ अधूरी पड़ी है, उनके बारे में लिख कर दे दें, उनको हम कम्पलीट कराएंगे। हम पूरे प्रान्त में पीने का पानी दे रहे हैं। सोनीपत अलग थोड़े ही है।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जुलाना में 1995 में बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। उसके बाद जुलाना कांस्टीच्यूएंसी में कम से कम 25 गांवों में पीने के पानी की बहुत असुविधा है। लोगों को गर्मी के मौसम मे पीने के पानी का बड़ा दुख है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जुलाना हल्के में पीने के पानी की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, बाढ़ के कारण सारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर जहां-जहां पर वाटर टैंक्स का नुक्सान हुआ था उन सब वाटर टैंक्स की मुरम्मत करवा दी गई है। पीने के पानी का सारी स्टेट में बड़े सुचारू रूप से काम चल रहा है।

Construction of Roads

***259. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the construction work of the road from village Baland to Karauntha in Rohtak district is lying incomplete ; and

(b) if so, the time by which the construction of the road as referred to in paart (a) above is likely to be started/completed ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes Sir,

(b) Balance portion of Road is likely to be completed by the end of, June 1997, subject to availabillity of funds.

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, वैसे तो मंत्री जी रोहतक जिले से ताल्लुक रखते हैं इसलिए इनको रोहतक जिले के बारे में अच्छी प्रकार से ज्ञान है। रोहतक जिले की जितनी भी सड़कें हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि करौंथा से बालन्द सड़क के बिना भेदभाव के प्रायर्टी बेस पर बना दिया जाएगा। मंत्री जी हमारे भाई हैं।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सवाल के जवाब को पढ़ने का कष्ट करें मैंने उसमें आश्वासन दिया हुआ है। (शोर)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बिना भेदभाव के उस सड़क को बनाएं। हम भाई के साथ नैपोटिज्म नहीं करेंगे। सब भाईयों का हिसाब से काम करेंगे। यह थोड़े ही है कि भाई है तो उसको सारी चीज दे दो। (हंसी)

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो मंत्री जी से उस सड़क की प्रायर्टी बेस पर बनाने का आश्वासन चाहता हूँ।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को लिखित रूप में यह आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे फण्डज अवेलेबल होंगे इस सड़क को बनाएंगे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पढ़ लिया था कि धन की उपलब्धता पर इस सड़क को बनाया जाएगा।

श्री धर्मवीर यादव : यह आश्वासन लिखित रूप में ही दिया गया है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पिछले 10 सालों से दादरी हल्का और आपके एरिया का विजिट करते आ रहे हैं। मायना साहब तो इनसे नई सड़क बनवाने के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि दादरी हल्के में बाढ़ के कारण जो रोडज़ खत्म हो गई हैं टूट गई हैं उनकी रिपेयर कब तक हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, हम कोई नई सड़क की मांग नहीं कर रहे।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष मोहदय, पैसे की अवेलिविलिटी पर जितनी भी रोड़ज की रिपेयर की आवश्यकता होगी, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय पी०डब्ल्यू०डी० मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 1995 में भिवानी जिले में बड़ी भारी भयंकर बाढ़ आई थी, लाई गई थी उस समय वहां पर काफी सड़कें टूट गई थी। हो सकता है कि उन सड़कों की कागजों में मुरम्मत कर दी गई हो लेकिन असल में हुई नहीं थी। क्या मंत्री महोदय उन टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत शीघ्र हो जाएगी, आश्वासन देंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष मोहदय, बाढ़ में जितनी भी सड़कें टूटी थीं, उन सब को प्रायर्टी पर रिपेयर किया जाएगा।

Opening of Government College at Ambala Cantt.

***269 Shri Anil Vij :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governeent to open a Government College at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) इस बारे कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले दिनों मुख्य मंत्री जब अम्बाला छावनी गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 + 2 स्कूल में अम्बाला छावनी में जमीन उपलब्ध है, वहां पर कालेज बनाया जाएगा। वहां पर पिछले अनेक वर्षों से केवल 3 कालेजिज ही हैं,जबकि वहां पर स्कूलों की संख्या बहुत अधिक हुई है। वहां पर और कहीं पर तो जमीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसी स्कूल में जमीन उपलब्ध है, क्योंकि उस स्कूल के पास काफी जमीन है। उसी में कालेज का निर्माण कर दिया जाएगा। मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री बंसी लाल जी का जो वाक्य होता हो, वह ब्रह्म वाक्य होता है यानि जो ये आश्वासन देते हैं उसे पूरा किया जाता है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर कालेज बनाने का आश्वासन दे दिया था तो अब मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने 'ना' का उत्तर क्यों दिया है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि हम चौधरी बंसी लाल जी के एक-एक अक्षर की पालना करते हैं और उनकी बातों को पूरा करते हैं, इसीलिए उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा भी है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी अम्बाला छावनी गए थे तो वहां की जनता ने और अनिल विज जी ने वहां पर कालेज बनाये जाने की मांग रखी थी। उसके बाद हमने इस बारे में सारा सर्वेक्षण करवाया। अध्यक्ष महोदय, इस समय अम्बाला जिले में 10 महाविद्यालय चल रहे हैं। ये हैं :—

1. जी०एम०एन० कालेज, अम्बाला छावनी, 2. एस०डी० कालेज, अम्बाला कैंट, 3. आर्य गर्ल्ज कालेज, अम्बाला कैंट, 4. डी०ए०वी० कालेज, अम्बाला शहर , 5. एस०ए०जैन कालेज, अम्बाला शहर, 6. एस०डी० कालेज (महिला), अम्बाला शहर, 7. एस०एस०डी०ए०वी० कालेज आफ एजुकेशन अम्बाला शहर, 8. एस०एम०एस० लुबाना खालसा गर्ल्ज कालेज, बराड़ा, 9. गुरु नानक खालसा कालेज, पंजोखड़ा साहिब (अम्बाला), 10. एम०पी०एन० कालेज, मुलाना।

अध्यक्ष महोदय, अम्बाला हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण नगर है। वहां की जनता ने करोड़ों रुपये इक्ट्ठे करके एक अस्पताल बनाया है और उसमें अनिल विज जी ने भी काफी सहयोग दिया है और वहां पर एक भवन भी बनाया है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इस आने वाले वर्ष में इस पर विचार किया जाएगा।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, शायद अनिल विज जी कुछ और जानना चाहते हैं। मैं खुद वहां पर गया था तो मुझे बताया गया था कि वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है। जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसी में ही कॉलेज बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात एजुकेशन मिनिस्टर साहब को बता नहीं पाया था।

श्री विजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा चौधरी देवी लाल जी के राज में नौलथा कांस्टीच्युऐंसी में कॉलेज बनाने के लिए लोगों ने पैसे इक्ट्ठे किये थे। उनमें से आधे पैसे तो *** ले गया लेकिन 15 लाख के करीब की राशि

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दो आदमियों के नाम जमा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या यह बात उनके नोटिस में है और यदि है तो क्या वहां पर कॉलेज बनवाने के बारे में ये विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो आधे पैसे खाने वाले का नाम लिया है वह रिकार्ड न जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भाई बिजेन्द्र सिंह कादयान को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में लोगों को शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव है। वर्ष 1967 में यहां पर लिट्रेसी परसैंटेज 26 था तथा हरियाणा की जनता जनार्दन का 55.58 परसैंट लिट्रेसी परसैंटेज आया है। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि लोग अपनी-अपनी कमाई में से विद्यालय और महा-विद्यालय खुलवाने के लिए खर्च करते हैं तथा धन एकत्रित करते हैं तथा संस्थाएं खोलने के लिए अपना योगदान देते हैं। विशेषकर नौलथा के बारे में जो इन्होंने कहा है, जो कुछ भी इनके ध्यान में है, ये हमें भिजावें, हम इस पर जो भी हो सकती है, वह कार्यवाही करवाएंगे।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के विचाराधीन इस प्रकार की कोई परपोजल है कि जो कस्बे शहरों से 35-40 किलो मीटर की दूरी पर हैं, वहां पर भी कॉलेज खोले जाएं। जिस प्रकार सांपला रोहतक से करीब 35 किलो मीटर की दूरी पर है और वहां पर कोई कॉलेज नहीं है। वहां के लोग अपना पैसा इकट्ठा करके कॉलेज की स्थापना करवाना चाहते हैं। क्या मंत्री जी इस बारे में कोई कार्यवाही करवाएंगे ? (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भाई बलवन्त सिंह मायना जी के चुनाव क्षेत्र में मैं गांव दातौड़ में इसी सप्ताह हो कर आया हूँ। सांपला के दूसरे लोग और वहां से हमारी प्रत्याशी बहन बसन्ती देवी, जो कि सर छोटू राम की बेटी हैं, भी उस सभा में मौजूद थीं। उन्होंने भी आग्रह किया था। सांपला में सर छोटू राम के नाम से एक संस्था वहां पर बनाई है और अब बलवन्तसिंह मायना भी कह रहे हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए इन्हें बताना चाहता हूँ कि यह बात मेरी जानकारी में है और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

Repair of Roads and Provision of Proper Drainage

*** 368. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the roads of villages Barhana & Dubaldhan district Rohtak are damaged every year in rainy season due to the non-existance of proper out lets; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads and to make a provision for proper drainage ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Due to an inadequate drainage system, the problem of flooding gets aggravated in the villages of Barhana and Dubaldhan in District Rohtak.

[Shri Dharamvir Yadav]

(b) There is a proposal for construction of a Drain in village Barhana. However, at present there is no proposal for construction of Drain in Village Dubaldhan.

Dr. Virender Pal Ahlawat : Mr. Speaker Sir, I would like to know from the worthy minister for Public works that in his reply it has been mentioned that they are going to construct a drain. A drain means an outlet on one side of the road. Whether there is a provision of constructing the drain on both sides of the road or only one side of the road ? First of all I would like to clear this point. The second question is I would also like to know the time by which the proposal for the construction of roads and drain in Village Dubaldhan will be taken up. The thrid point I would like to ask from the Minister is that this a common problem in all the villages of Hayana. Whether the government is thinking to bring this proposal for all the villages through which road passes ?

Shri Dharamvir Yadav : Speaker, Sir, at present, the proposal for construction of drain is only on one side of the road and for the kind infromation of the Hon'ble Member, I may tell the House that the drain is to be constructed by the Panchayat Department and not by the P.W.D.

Mr. Speaker : Anything more, Mr. Ahlawat ?

Dr. Virender Pal Ahlawat : Sir, recently I happened to visit the village and I found that some portion of the drain had been constructed on one side of the road. I wanted to know the fate of the people who are living on the other side of the road about which I have not been informed.

(Not replied.)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने भी शहरों के रोड्ज़ हैं, उनके किनारों पर निकासी न होने की वजह से पानी आ जाता है, लोग भी वहां पर पानी फेंक देते हैं जिस वजह से वे सड़कें टूट जाती है, तो क्या ये वहां पर कंकरीट की सड़कें बनाने का आश्वासन देंगे ताकि वे सड़कें बार-बार न टूटें और ऐसा करने से सरकार का नुक्सान होने से भी बच जाएगा।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में पंचायत डिपार्टमैंट से पैसा आने पर हम विचार करेंगे।

Primary Health Centre, Badli

***283. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state —

(a) whether the construction work of the building of the Primary Health Centre, Badli has been completed; and

(b) if so, the time by which it is likely to start functioning ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) जी हां, सिवाय आन्तरिक रोड़ तथा पार्किंग के जोकि 1997-98 में पूर्ण हो जाएंगे।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1997-98 में कार्य करना आरम्भ कर देगा।

श्री रामफल कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से बताना चाहूँगा कि हमारे भुआना गांव में पी०एच०सी० की जो बिल्डिंग है, एक साल पहले की बनी हुई है। आज भी उसका स्टाफ प्राईवेट बिल्डिंग में बैठता है। वहां पर कोई स्टाफ नहीं होने की वजह से वहां से लोग खिड़कियां तक चुरा कर ले गये हैं। क्या ये जो स्टाफ की बात कर रहे थे, उसे वहां पर स्टाफ भेजने का कष्ट करेंगे।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उस बारे में मैं इनको आपके द्वारा बताना चाहूंगा कोई भी ऐसी बिल्डिंग, जो क्षति ग्रस्त हो, वहां पर लोगों की जान का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। दूसरे जो इन्होंने स्टाफ की कमी की बात कही है, हम 205 नए डाक्टर्ज़ भर्ती करने जा रहे हैं, उसके बाद कहीं पर भी डाक्टर्ज की, नर्सों की और दूसरे स्टाफ की कमी नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा रखा है, अगर ये भी वहां के बारे में हमें लिखर दरख्वास्त भेजेंगे, तो हम उस बारे में भी देख लेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, दादरी का आपके जिले से भी सम्बन्ध है। दादरी के अन्दर एक बहुत पुराना होस्पीटल है और वहां बाढ़ आने की वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। क्या वहां पर नई बिल्डिंग बनाने का सरकार की तरफ से कोई प्रावधान है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : स्पीकर सर, इस समय हमारी सरकार दस अस्पताल, 9 सी०एच०सी० एवं 25 पी०एच०सीज० बनाने जा रही है और इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। जहां तक सदस्य ने दादरी के बारे में सवाल किया है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि वहां का मामला अभी हमारे ध्यान में नहीं है लेकिन अगर ये अपनी तरफ से इसके बारे में लिखकर हमें दे देंगे तो हम जरूर वहां पर बनवा देंगे।

तारांकित प्रश्न सं० 288

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री बन्ता राम बाल्मीकि, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Water Works of village Bhaini Bhairon

*** 296 Shri Balbir Singh :** Will the Minister for public Health be please to state —

(a) whether it is fact that the water tank in village Bhaini Bhairon, district Rohtak has already been constructed; and

(b) if so, the time by which it is likely to be made functional ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ) :

(क) जी, हाँ।

(ख) नहरी पानी की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी तो बहुत जरूरी है और फिर वहां पर टैंक भी पहले से ही बना हुआ है तो फिर इसको चालू करवाने में इनको क्या दिक्कत है ? अध्यक्ष महोदय, सरकार को अन्य बातों के अलावा पीने के पानी का प्रबन्ध तो अवश्य ही करना चाहिए।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, यह भैणी भैरों टैंक अप्रैल, 1990 में मंजूर हुआ और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ तथा दिसम्बर, 1995 में इस पर काम पूरा हो गया। इसके बाद इसमें पानी भैणों महाराजपुर से आता था। डेढ़ साल इसको बने हुए हो गये और प्रोपर मेहम हल्के का एम०एल०ए० मंत्री भी रह लिया। लेकिन वे यह काम पूरा नहीं करवा पाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि जुई कैनाल से एक छोटा रजबाहा जाता है, जिसकी लम्बाई साढ़े सात किलोमीटर है। यह रजबाहा साढ़े तीन किलोमीटर तक टिब्बों में से गुजर कर जाता है। सर, यह रजबाहा नहीं बल्कि एक नाला है क्योंकि इसका बेस नीचे से सिर्फ डेढ़ फुट रह गया है। जब बरसात होती है तो यह भर जाता है। इसके अलावा यदि थोड़ी सी भी हवा तेज चल जाए तो यह रेत से भी भर जाता है। स्पीकर सर, यह पोरली पोलिटिकल रूप से बनाया गया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि यह बना दिया गया तो इस टेल के नीचे जहां कभी पहले भी पानी नहीं जाता था, पानी पहुंच जाएगा और यदि ऐसा हुआ तो हमारे खेतों में भी पानी जाएगा तथा हमारे खेत पानी से भर जाएंगे। स्पीकर सर, आपको ऐसी बातें एक जगह नहीं अनेकों जगहों पर मिलेंगी। इसलिए वहां पर थोड़ा पानी तो जाता है लेकिन इतना पानी नहीं जाता है कि वहां पर पूरा वाटर बर्क्स भर दिया जाए। इसकी काफी सफाई करवायी गयी लेकिन थोड़े ही दिनों बाद यह फिर भर जाता है। इसलिए हम भैणों महाराजपुर से ही इसकी पानी की सप्लाई जारी रखे हुए हैं। यदि वहां पर तीन टंकियां और बना दी गयीं तो इसके बाद वहां पर पूरा पानी मिलेगा। ये भिवानी जिले में मोखरा की बात करते हैं। आप वहां पर लोहारू साईड में जाकर देखें। तोशाम हल्के के अंदर भी कुछ वाटर बर्क्स ऐसे हैं कि गर्मियों के दिनों में वहां भी दिक्कत रहती है। यह सरकार बनने के बाद कुछ जहां वाटर-बर्क्स बने हुए थे, पानी जाता नहीं था अब वहां पानी जाने लगा है। बहादुरगढ़ एरिया के गांव कराठी और नीलोहेठी ईसरहेड़ी आदि इन गांवों में पानी नहीं जाता था लेकिन नालों की सफाई करने के बाद और रजबाहों की सफाई करने के बाद पानी जाने लगा है। इसी प्रकार झज्जर सब-डिवीजन के अंदर सोरठा, बाराहेड़ी और भैणी भैरों इन गांवों में भी पानी नहीं जाता था लेकिन नालों और रजबाहों की सफाई के बाद पानी जाने लग रहा है। फिर भी एक दो रजबाहे ऐसे हैं, जिनमें पानी पहुंचाना असंभव बात है। सिर्फ आपके मेहम हल्के में ही बल्कि तोशाम और लोहारू हल्कों में भी यही दिक्कत है। आपका गांव तो दिल्ली की तलहटी में है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। जो बात होगी वह बात मानेंगे। आपकी सरकार आने के बाद कोशिश हुई है। पिछली सरकार ऐसी थी कि सब काम गोल कर रखे थे। मंत्री जी के भाई ने वह बनवाई थी, उसमें पूरा माल नहीं लगा था लेकिन यह सरकार आने के बाद कोशिश हुई है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पानी का प्रबन्ध जरूर किया जाए।

श्री जगन नाथ : पिछली सरकार ने वह सारा काम गोल किया तो आपने उस मंत्री को गोल कर दिया। यानी उसकी गांठ बांध दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पानी का पूरा प्रबन्ध करेंगे।

Sugarcane crushed during Current Season

*** 309. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) the names of the Sugar Mills in cooperative sector and private sector which are in operation during the current crushing season; and

(b) the monthwise quantity of sugarcane crushed by each Sugar Mill during the period referred to in part (a) above ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) एक तालिका जिसमें चालू पिराई मौसम के दौरान प्रत्येक एवं

(ख) चीनी मिल का नाम तथा उस द्वारा मासवार गन्ने की पिराई की गई मात्रा दर्शाई गई है, सदन के पटल पर रखी जाती है।

तालिका

(मात्रा लाख क्विंटल में)

क्रम	चीनी मिल का नाम	नवम्बर, 96 के दौरान	दिसम्बर, 96 के दौरान	जनवरी, 97 के दौरान	फरवरी, 97 के दौरान
सहकारी क्षेत्र					
1.	शाहबाद सहकारी चीनी मिल लि० शाहबाद	4.01	10.23	10.21	9.49
2.	करनाल सहकारी चीनी मिल लि० करनाल	6.67	8.00	6.00	6.80
3.	पानीपत सहकारी चीनी मिल लि० पानीपत	1.77	4.85	4.43	3.87
4.	सोनीपत सहकारी चीनी मिल लि० सोनीपत	5.13	5.15	3.85	5.11
5.	रोहतक सहकारी चीनी मिल लि० रोहतक	4.48	5.49	5.25	4.95
6.	पलवल सहकारी चीनी मिल लि० पलवल	4.93	5.25	3.48	4.57
7.	जीन्द सहकारी चीनी मिल लि० जीन्द	5.78	5.98	3.81	5.57
8.	महम सहकारी चीनी मिल लि० महम	1.14	6.55	4.61	6.10
9.	कैथल सहकारी चीनी मिल लि० कैथल	5.17	6.70	4.91	5.74

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

10.	भूना सहकारी चीनी मिल लि०, भूना	1.24	5.90	3.54	5.18
	उप जोड़	40.32	64.10	50.09	57.38
निज़ी क्षेत्र					
11.	सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर	16.82	22.11	25.88	20.12
12.	पिकाडली एग्रो इन्डस्ट्रीज लि०, गांव भादसी ज़िला करनाल	—	3.59	6.79	6.64
13.	नारायणगढ़ चीनी मिल लि०, गांव बनौदी ज़िला अम्बाला	—	0.86	5.18	6.23
	उप जोड़	**16.82**	**26.56**	**37.85**	**32.99**
	कुल जोड़	**57.14**	**90.66**	**87.94**	**90.37**

28.2.97 तक कुल पिराई की गई मात्रा = 326.11 लाख क्विंटल

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि करनाल शूगर मिल में दिसंबर, 1996 में 8 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हुई थी जब कि जनवरी, 1997 के महीने में यह पिराई 2 लाख क्विंटल घट गई। इसी प्रकार फरवरी में 6.80 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हुई मतलब यह 1.20 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई कम हुई। इसी प्रकार पानीपत शुगर मिल है इसमें भी दिसम्बर, 1996 में 4.85 लाख क्विटंल पिराई हुई जनवरी, 1997 में इसमें 4.43 लाख क्विंटल की पिराई की गई। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए। स्टेटमैंट मत दीजिए।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पिराई कम होने का कारण क्या है ? आपकी शुगर मिलें मुनाफे में चल रही हैं या घाटे में चल रही हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी मनी राम जी ने जो सवाल किया है, उसका जवाब वे स्वयं भी जानते हैं कि मिलों में पिराई इस साल कम क्यों हुई है। सारा हरियाणा यह अच्छी तरह से जानता है कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी पिराई के सीज़न में सारे हरियाणा की शुगर मिलों में घूमते रहे और कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाते रहे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि गन्ने की पिराई सारे हरियाणा में ठीक तरीके से चल रही है। (शोर एवं विघ्न) हमने तकरीबन पूरे हरियाणा में समय से 15 दिन पहले मिलें चलवाई हैं।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Allotment of Shed

***305. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Shed constructed by H.S.A.M.B. at Bhiwani has not been allotted to the fruit and vegetable sellers so far; and

(b) if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the aforesaid Shed is likely to be allotted ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) जी हां, यह सही है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल तथा मार्किट कमेंटी द्वारा सब्जी मंडी भिवानी में निर्मित शैड फल तथा सब्जी विक्रेताओं को अभी तक आबंटित नहीं किया गया।

(ख) मंडियों में प्लाटों / स्थानों के आबंटन हेतु नीति के विचाराधीन होने के कारण इन स्थानों का आबंटन रुका हुआ है। उक्त नीति के निर्णय उपरान्त स्थानों का आबंटन बिना किसी देरी के कर दिया जाएगा।

Upgradation of Schools

*** 332. Shri Sri Krishan Hooda :** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the schools of villages Polangi and Mungan from Middle to High; and

(b) if so, the time by which the schools as referred to in part (a) above are likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Share in the Water of Dohan & Krishnawati Rivers

*** 340 Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state —

[Shri Kailash Chandet Sharma].

(a) whether Government is aware of the fact that the water table in Mohindergarh district is going down due to the construction of Dam on Dohan & Krishnawati Rivers by Rajasthan Government; and

(b) if so the steps so far taken or proposed to be taken to get the share of Haryana State in the water of aforesaid rivers ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी हाँ।

(ख) इस मुद्दे को राजस्थान सरकार एवं अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ उठाया गया है।

Damage Caused to the Crops

***317 Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Minister of State for Forests be pleased to state :—

(a) whether it is fact that Antelopes/Neel Gayan/stray cattle are causing damage to the crops and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken in this regard ?

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्री सुभाष चौधरी) :

(क) जी, हां ।

(ख) हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 61 (2) के अन्तर्गत प्रविधियों में तबदीली करने की शक्तियां पुनः राज्य सरकारों को प्रदत करने के लिए अनुरोध किया है। इन शक्तियों के अन्तर्गत, जो कि 1991 में वापिस ले ली गई थी, ऐसे वन्य प्राणी जो मानव जीवन या सम्पत्ति, जिसमें फसलें भी शामिल हैं, को नुकसान पहुंचाते थे, को वरमिन घोषित किया जा सकता था ताकि बिना प्रतिबन्ध के उन्हें मारा जा सके। फिलहाल सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की प्रार्थना पर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोज़ को मारने के लिए वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) (बी) के अन्तर्गत परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

Setting up of 33KV Sub-Station at Kakrod

***346. Shri Birender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the H.S.E.B. to set up a

33KV Sub Station at Village Kakrod district Jind; if so, the time by which the said Sub Station is likely to be set up ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : वर्तमान समय में जिला जीन्द के काकरोद गांव में एक उपकेन्द्र स्थापित करने की कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं है।

Share of Farmers in Trees

***364 Shri Bhagi Ram :** Will the Minister of State for Forest be pleased to state whether any share is given to the farmers in the sale of trees planted on the sides of roads and canals adjacent to their fields in the State; if so, the extent thereof ?

Minister of State for Forest (Shri Jagdish Yadav) : No, Sir.

Subsidy Given on Sprinkler sets

*** 408. Shri Jagdish Nayar :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state —

(a) whether any case of mis-appropriation/embezzlement in providing of subsidy to the farmers in the purchase of sprinkler sets during the years 1981-82 to 1987-88 has been detected by the department in the years 1988-89 and 1989-90; if so, the names of officials with designation involved therein; and

(b) whether any action has been taken or proposed to be taken against the officials as referred to in part (a) above ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान सप्लाई किए गये फव्वारा सैटों पर सबसिडी की अदायगी के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं बारे सरकार को पता चला था। इस मामले में संलिप्त कर्मचारियों की सूची उनके पद नाम सहित सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) दो एफ०आई०आर० दर्ज करवाई गई थी। दो राजपत्रित अधिकारियों और 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित भी किया गया था। तत्पश्चात आपराधिक मामले वापिस ले लिए गये। हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) अधिनियम, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत 131 कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किए गए। इस केस में संलिप्त सभी राजपत्रित अधिकारियों को भी हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) अधिनियम के नियम-8 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी करने का निर्णय ले लिया गया है।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

सूची

फव्वारा सथन्त्रों पर अनुदान की अदायगी के केसों के सम्बन्ध में शामिल सहायक भूमि संरक्षण अधिकारियों की सूची :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम
सर्वश्री	
1.	जयवीर सिंह
2.	एल०सी० यादव
3.	हरीश चन्द्र कटारिया
4.	पूर्ण सिंह राणा
5.	बी०एस० डागर
6.	जे०सी० डबास
7.	टी०सी० अरोड़ा
8.	जे०सी० बिश्नोई
9.	जैड० ए० अन्सारी
10.	जी० एस० राणा
11.	मैम्बर सिंह बलधाण
12.	धर्मपाल दहिया
13.	महीपाल
14.	गंगा राम

फुव्वारा सैटों पर अनुदान की अदायगी के केसों के सम्बन्ध में कृषि विकास अधिकारियों की सूची :—

क्रं० सं०	कर्मचारी का नाम
सर्वश्री	
1.	घनश्याम दास
2.	सतपाल
3.	महेश गिरी
4.	सूरज भान
5.	हरी राम
6.	एस०के० छाबड़ा

1	2
7.	ओम प्रकाश
8.	उदय भान
9.	राम किशन
10.	महावीर सिंह
11.	गुलबीर सिंह
12.	विजेन्द्र त्यागी
13.	अरूण कुमार शर्मा
14.	सुखबीर सिंह देसवाल
15.	जय नारायण
16.	सतबीर सिंह
17.	रमेश चन्द मक्कड़
18.	महाबीर सिंह
19.	सूरज भान
20.	ओम प्रकाश
21.	वेद प्रकाश
22.	ओम प्रकाश राणा
23.	जगदीश
24.	राम कुमार हुड्डा
25.	निहाल सिंह
26.	योगिन्द्र सिंह
27.	राम कुमार
28.	एस०पी० यादव

फुव्वारा सैटों पर अनुदान की अदायगी के केसों के सम्बन्ध में शामिल लेखाकारों की सूची :—

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम
सर्वश्री	
1.	घनश्याम दास गुप्ता
2.	राम चन्द्र गुप्ता
3.	तिलक राज
4.	देवेन्द्र नाथ दुआ
5.	जय प्रकाश वर्मा
6.	सुरेशचन्द
7.	नारायण दास

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

फुव्वारा सैटों पर अनुदान की अदायगी के केसों के सम्बन्ध में शामिल प्रारूपकारों की सूची :—

क्रम० सं०	कर्मचारी का नाम
सर्वश्री	
1.	ओम नारायण
2.	चरणजीत चोपड़ा
3.	राम भगत
4.	राम निवास
5.	ओम प्रकाश
6.	नरेश कुमार
7.	राम फल
8.	मान सिंह

फुव्वारा सैटों पर अनुदान की अदायगी के केसों के सम्बन्ध में शामिल कृषि निरीक्षकों/सर्वेयरों की सूची :—

क्रम० सं०	कर्मचारी का नाम
सर्वश्री	
1.	रणजीत सिंह, सर्वेयर
2.	बाबू लाल, ए० आई०
3.	सुलतान सिंह, ए० आई०
4.	होशियार सिंह, ए० आई०
5.	जय सिंह यादव, ए० आई०
6.	प्रताप सिंह, ए० आई०
7.	सुरेन्द्र सिंह, ए० आई०
8.	राजेन्द्र सिंह, ए० आई०
9.	सुरजभान, ए० आई०
10.	नानक चन्द, ए० आई०
11.	फूल चन्द, ए० आई०
12.	राम पत, ए० आई०
13.	करतार सिंह, ए० आई०
14.	हरी सिंह, ए० आई०
15.	सनबत सिंह, ए० आई०
16.	जय भगवान, ए० आई०
17.	राजबीर सिंह, ए० आई०
18.	अशोक कुमार, सर्वेयर

1	2
19.	बसन्त लाल, ए० आई०
20.	धर्मपाल, ए० आई०
21.	उमेद सिंह, ए० आई०
22.	बीर सिंह, ए० आई०
23.	जगदीश सिंह, ए० आई०
24.	शिव नारायण, ए० आई०
25.	जय लाल, ए० आई०
26.	धर्मवीर, ए० आई०
27.	ओम प्रकाश, ए० आई०
28.	जय चन्द, ए० आई०
29.	हवा सिंह, सर्वेयर
30.	राम प्रसाद, ए० आई०
31.	महीपाल सिंह, ए० आई०
32.	रणबीर सिंह, ए० आई०
33.	धर्मवीर, सर्वेयर
34.	चन्दू लाल, ए० आई०
35.	लाल सिंह, ए०आई०
36.	महेन्द्र सिंह, ए०आई०
37.	ओम प्रकाश, ए०आई०
38.	सज्जन सिंह, ए०आई०
39.	प्यारे लाल, सर्वेयर
40.	राम नारायण, ए०आई०
41.	दुली चन्द, सर्वेयर
42.	आत्मा सिंह, सर्वेयर
43.	गजराज सिंह, ए०आई०
44.	लक्ष्मण दास, सर्वेयर
45.	जागे राम
46.	राम प्रसाद, ए०आई०
47.	अमीर चन्द, ए०आई०
48.	दया नन्द, ए०आई०
49.	हरी राम, ए०आई०
50.	राम किशन, ए०आई०
51.	ओम प्रकाश शर्मा, ए०आई०
52.	नरेश कुमार, ए०आई०
53.	त्रिलोचन सिंह, ए०आई०

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

1	2
54.	हेम चन्द्र, ए०आई०
55.	जिले सिंह, ए०आई०
56.	राम निवास, ए०आई०
57.	रघुबीर सिंह, ए०आई०
58.	धन सिंह, ए०आई०
59.	उमेद सिंह, ए०आई०
60.	सुरेश कुमार, ए०आई०
61.	सूरत सिंह, ए०आई०
62.	सूरज भान ए०आई०
63.	समुन्द्र सिंह, ए०आई०
64.	ओम प्रकाश रहेजा, ए०आई०
65.	ओम प्रकाश, ए०आई०
66.	जग राम, ए०आई०
67.	दया नन्द, ए०आई०
68.	महीपाल ए०आई०
69.	राजेन्द्र सिंह, ए०आई०
70.	शीशपाल सिंह, ए०आई०
71.	भागे राम, ए०आई०
72.	मान सिंह, ए०आई०
73.	महाबीर सिंह, ए०आई०
74.	बलवान सिंह, ए०आई०
75.	करतार सिंह, ए०आई०
76.	इन्द्र सिंह, ए०आई०
77.	राम निवास, ए०आई०
78.	तुलसी राम, ए०आई०
79.	भूप सिंह, ए०आई०
80.	हवा सिंह, ए०आई०
81.	जीत सिंह, ए०आई०
82.	बिशन लाल, ए०आई०
83.	रण सिंह, ए०आई०
84.	कंबल सिंह, ए०आई०
85.	रणधीर सिंह, ए०आई०
86.	दरिया सिंह, ए०आई०
87.	बिशन लाल, ए०आई०
88.	नरेन्द्र सिंह, ए०आई०

वर्ष 1997-98 का बजट पेश करना

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will present the Budget for the year 1997-98.

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के सामने वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान पेश करने जा रहा हूँ।

2. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में प्रमुख संरचनात्मक तथा बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे लाइसेंसिंग व आर्थिक नियन्त्रण के माहौल से उभर रही है। आर्थिक उदारीकरण, लाईसेंसिंग प्रथा समाप्त करने, विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियन्त्रण को समाप्त करने, विदेशी पूंजी निवेश, सूचना क्रान्ति तथा विदेशी व्यापारिक प्रतिबन्धों के समाप्त होने के कारण भारतीय अर्थ-व्यवस्था को नई दिशा मिली है। परिवर्तन की हवा सब ओर चल रही हैजो इस बात का संकेत है कि भारतीय की अर्थ व्यवस्था विश्व के आर्थिक ढाँचे के साथ समन्वय की दिशा मे बढ़ रही है।

3. हरियाणा जैसा आर्थिक दृष्टि से गतिशील राज्य भी इस बदले हुए आर्थिक माहौल से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहा है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है तथा आर्थिक विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

4. राज्य की अर्थ-व्यस्था पिछले वर्ष की कठिनाइयों से निश्चित रूप से उभरी है एवं आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रही है। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97 की प्रतियां माननीय सदस्यों में बांटी जा चुकी हैं । यह सर्वेक्षण गत वर्षों के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। अनुमानों के अनुसार, राज्य की सकल आय में 1980-81 के स्थिर मूल्यों के आधार वर्ष 1995-96 में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ्डि वर्ष 1995-96 में 7406 करोड़ रुपये हुई है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य की आय वर्ष 1994-95 में 7268 करोड़ रुपये की आय से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 24411 करोड़ रुपये से 14.3 प्रतिशत की दर से बढ़ कर वर्ष 1995-96 में 27903 करोड़ रुपये हो गई। क्षेत्रवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर में, मूल्यों (1980-81) के आधार पर, प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में वर्ष 1995-96 में अभूतपूर्व बाढ़ और अत्याधिक वर्षा से हुए नुकसान के कारण 6.1 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में 8.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।

5. 1980-81 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वस्तुतः वर्ष 1995-96 में 3670 रुपये होने का अनुमान है, जबकि यह 1994-95 में 3674 रुपये थी। वर्तमान मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1994-95 में 12242 रुपये के मुकाबले में वर्ष 1995-96 में 13770 रुपये होने का अनुमान है।

6. मुद्रा स्फीति की दर राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर ही इस अवधि के दौरान बढ़ती रही है। अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) मार्च, 1995 में 293 से 8.9 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 1996 में 319 हो गया। यह नवम्बर, 1996 में पुनः 9.4 प्रतिशत

[श्री चरण दास]

बढ़कर 349 हो गया। इसी प्रकार हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100) मार्च, 1995 व मार्च 1996 की अवधि के दौरान 270 से 5.2 प्रतिशत की दर से बढ़कर 284 हो गया। यह 13.4 प्रतिशत की दर से पुनः बढ़कर नवम्बर, 1996 में 322 हो गया।

7. बजट अनुमान 1996-97 के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार 535 करोड़ रुपये का सीधा पूंजी निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के पूंजी निर्माण में राज्य के योगदान के कारण 487 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजी निर्माण होने का अनुमान है। अतः 1996-97 के दौरान 1022 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निर्माण होने का अनुमान है।

केन्द्रीय सरकार से अन्तरण/सहायता

8. केन्द्र से आर्थिक सहायता राज्य सरकार की विभिन्न विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए आय का एक मुख्य साधन है। केन्द्र से करों के रूप में जो आय प्राप्त होती है। वह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को उपलब्ध होती है। 10वें वित्त आयोग की सिफारशें आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के पक्ष में हैं तथा हरियाणा जैसे विकसित राज्यों को इन सिफारिशों के अनुसार कम आर्थिक सहायता मिलती है। वर्ष 1995 से 2000 की अवधि के दौरान सभी राज्यों के लिए 26,643 करोड़ रुपये के कुल अन्तरण में से हरियाणा का हिस्सा केवल 2793 करोड़ रुपये का है, जो की कुल अन्तरण का 1.23 प्रतिशत है, यह हरियाणा की जनसंख्या (1.97 प्रतिशत) तथा क्षेत्र (1.35 प्रतिशत) के अनुपात से भी कम है। तदनुसार वर्ष 1996-97 में केन्द्र सरकार से हरियाणा राज्य को मिलने वाली राशि का प्रावधान संशोधित अनुमान 1996-97 में 423 करोड़ रुपये का और बजट अनुमान 1997-98 में 465 करोड़ रुपये का किया गया है। हरियाणा के लिए 1996-2000 की अवधि के लिए 40 करोड़ रुपये की स्पेशल प्रॉब्लम ग्रान्ट की सिफारिश की गई है। इसमें दिल्ली के आस-पास स्थित सैटेलाइटनगरों के विकास हेतु वर्ष 1996-97 के लिए 8 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1997-98 के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। आयोग द्वारा वर्ष 1996-2000 की अवधि के लिए 99.22 करोड़ रुपये के अनुदान की भी सिफारिश की गई है जिसमें वर्ष 1996-97 और वर्ष 1997-98 के दौरान पंचायतों और नगरपालिकाओं को 24.81 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बांटने के लिए भी शामिल किए गए हैं। इन अनुदानों का उपयोग पंचायती राजसंस्थाओं तथा नगरपालिकाओं द्वारा राज्य वित्त आयोग, जिस की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है, की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। योजना आयोग ने सामान्य सहायता के अभिन्न अंग के रूप में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए प्रति वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए 19.08 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 3.65 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के लिए हरियाणा राज्य को शहरी क्षेत्र स्लम ऐरिया सुधार हेतु प्रदान की गई है। मुख्य मंत्री जी के विशेष प्रयास से योजना आयोग ने वर्ष 1996-97 के दौरान 45 करोड़ रुपये और वर्ष 1997-98 के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता त्वरित सिंचाई लाभ योजनाओं के लिए एवं वर्ष 1997-98 के दौरान 30 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मेवात नहर परियोजना के लिए मंजूर की है।

9. राज्य में विदेशी सहायता से कई विकासकारी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 में 263 करोड़ रुपये और 1997-98 में 343.89 करोड़ रुपये की बाहा सहायता का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक योजना 1996-97

10. राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1996-97 के लिए 1430 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है जिसमें 829.29 करोड़ रुपये राज्यों के अपने संसाधनों और 600.71 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से जुटाये जाएंगे। इस राशि में 227.45 करोड़ रुपये साधारणतः मिलने वाली केन्द्रीय सहायता, 349 करोड़ रुपये विदेशी सहायता परियोजनाओं के लिए तथा 7.60 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्कीमों के लिए शामिल हैं।

11. चालू वर्ष के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति काफी कठिन रही। शराबबन्दी को लागू करने से 600 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व घाटा हुआ और इसके अतिरिक्त इस नीति को लागू करने पर अतिरिक्त खर्च हुआ। बाढ़ और अत्याधिक वर्षा से पीड़ित जनता की सहायता और पुनर्वास के लिये 95 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई और इसके अलावा राज्य में राजस्व प्राप्ति पर भी बुरा असर पड़ा। सरकारी कर्मचारियों को लाभ के रूप में 240.18 करोड़ रुपये मंजूर किये गए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ज़रूरी कार्यों पर भी इस वर्ष के दौरान खर्चा करना पड़ा जिस से कि राजस्व प्राप्ति एवं व्यय प्रभावित हुए।

12. हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछली सरकार द्वारा संसाधनों में की गई कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करने पड़े। चालू वर्ष के दौरान कुछ कर लगा कर और कुछ अन्य कदम उठा कर लगभग 340 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए। अल्प बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया एवं सार्वजनिक उपक्रमों को राज्य की योजना स्कीमों के लिए धन जुटाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। खर्च में किफायत को सख्ती से लागू किया गया ताकि योजनेतर खर्च में वृद्धि को रोका जा सके। वित्तीय बोझ को कुछ कम करने के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्तों और बोनस की रकम के कुछ हिस्से का नकद भुगतान न करके कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया गया।

13. वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना के लिए 1372.75 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दिया गया जोकि वर्ष 1995-96 के 1116.43 करोड़ रुपये के वास्तविक योजना खर्च से 22 प्रतिशत अधिक है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

14. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए 5700 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस परिव्यय के लिए 4713.64 करोड़ रुपये राज्य के अपने संसाधनों और 986.36 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से जुटाए जाने थे।

15. 1992-93 से 1995-96 तक आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 3627.52 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जो कुल परिव्यय का 63.6 प्रतिशत है। वर्ष 1996-97 के लिए, जो आठवीं योजना का अंतिम वर्ष है, संशोधित अनुमानों में 1372.75 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है। इस प्रकार, आठवीं योजना के दौरान 5000.27 करोड़ रुपये का खर्च प्रत्याशित है, जो कुल खर्च का 87.7 प्रतिशत होगा।

वार्षिक योजना, 1997-98

16. योजना प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए विकास की गति तेज करना और रोज़गार के बेहतर अवसर जुटाना, राज्य सरकार की मूल नीति रही है नौवीं पंचवर्षीय योजना के

[श्री चरण दास]

उद्देश्यों और प्रमुख क्षेत्रों के दृष्टिगत, राज्य की वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना के लिए 1575. 00 करोड़ रुपये के परिव्यय अनुमोदित किया गया है, इसमें से 903.28 करोड़ रुपये राज्य के अपने संसाधनों और 671.72 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से जुटाये जाएंगे। यह परिव्यय वर्ष 1996-97 के 1372.75 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

17. राज्य सरकार अपनी 1997-98 की वार्षिक योजना में सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं को उच्चतम प्राथमिकता देती रहेगी। इस क्षेत्र के लिए 477.82 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है, जो कुल परिव्यय का 30.3 प्रतिशत है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा के कारण हुई व्यापक हानि को देखते हुए सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। इस परियोजनार्थ 417.72 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो कुल परिव्यय का 26.5 प्रतिशत है। बिजली क्षेत्र के लिए 288.38 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जो कुल परिव्यय का18.3 प्रतिशत है। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों के लिए 105.13 करोड़ रुपये (6.7 प्रतिशत), परिवहन के लिए 154.92 करोड़ रुपये (9.8 प्रतिशत), ग्रामीण विकास के लिए 57.00 करोड़ रुपये (3.6 प्रतिशत), उद्योग तथा खनिज के लिए 27.92 करोड़ रुपये (1.8 प्रतिशत) अन्य क्षेत्रों के लिए 46.11 करोड़ रुपये (2.9 प्रतिशत) का परिव्यय रखा गया है। 1575.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 509.57 करोड़ रुपये की राशि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तथा 101.50 करोड़ रुपये की राशि मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए निर्धारित की गई है। कुल योजना खर्च का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किया जायेगा। मुझे आशा है कि योजना निवेश से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा और इससे आर्थिक विकास की गति भी बनी रहेगी।

मद्यनिषेध

18. जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार ने राज्य में प्रथम जुलाई, 1996 से पूर्ण मद्यनिषेध लागू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे खुशहाली के एक नये युग का शुभारम्भ होगा। समाज के सभी वर्ग, विशेषतौर पर महिलाएं, राज्य को एक नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थीं।

19. मद्यनिषेध को एक सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया ताकि समाज के सभी वर्गों को इस पावन कार्य के साथ जोड़ा जा सके। इस उद्देश्य के लिये मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शराबमुक्त हरियाणा समिति का गठन किया गया जिसमें मंत्रीगण, विभिन्न राजनैतिक दलों व समाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किये गये। यह समिति मद्यनिषेध को लागू करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं ताकि इस प्रोग्राम को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जा सके।

20. विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मदिरापान के कुप्रभाव की जानकारी देने के उद्देश्य से स्कूलों में मद्यनिषेध पर विशेष पाठयक्रम शामिल किये गये हैं। प्रसार के गैर परम्परागत माध्यम जैसे नुक्कड़ नाटक व सैमिनार इत्यादि नियमित रूप से स्वैच्छिक संस्थाओं एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को जन-अभियान बनाने के लिये महिला संगठनों, यूथ क्लबों एवं पंचायतों की मदद ली जा रही है।

21. मद्यनिषेध एवं आबकारी नाम से एक नये विभाग की स्थापना की गई है जो, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, जिसमें संशोधन करके कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, को लागू

करने का कार्य करेगा। इस अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार कुछ अपराधों, जिनमें एक निश्चित मात्रा से अधिक शराब उपलब्ध हो, को गैर जमानती बना दिया गया है। पकड़े गये नमूनों की जांच करने के लिए पांच नई प्रयोगशालाएं खोली गई हैं तथा 9 विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो कि अपराधियों के मामलों का तत्काल निपटारा करेंगे। मद्यनिषेध लागू होने से जनवरी, 1997 के अन्त तक कुल 29174 मुकद्दमें दर्ज किए गए हैं तथा 31594 व्यक्तियों को आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है। 7 लाख से भी अधिक शराब की थैलियां एवं बोतलें पकड़ी गई हैं तथा शराब की 697 भट्टियों को पकड़ा गया है।

22. माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि इस क्रांतिकारी कदम के कारण राज्य में अपराधों एवं दुर्घटनाओं की दर में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कमी आई है। 1-7-1996 से 31-12-1996 की अवधि के दौरान हत्याओं में 71 केसों की कमी आई है, घावात्मक केसों में 297 की कमी आई है, दुर्घटनाओं में 66 की, शराबियों के आतंक एवं गुण्डागर्दी के केसों में 292 की तथा धारा 107/151 सी०आर०पी०सी० के केसों में 572 की कमी आई है।

23. राज्य सरकार ने इसके लिए वर्ष 1996-97 में 14.99 करोड़ रुपये का प्रावधान किया ताकि शराबबन्दी को पूरी तरह से लागू किया जा सके।

बिजली

24. बिजली सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक मुख्य संसाधन है अतः राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को अत्यन्त महत्व दिया गया है। अप्रैल, 1996 से दिसम्बर 1996 तक की अवधि के दौरान औसत बिजली की सप्लाई 363.12 लाख यूनिट प्रतिदिन रही जोकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के मुकाबले 333.82 लाख यूनिट प्रतिदिन से अधिक है। दिसम्बर 1996 तक बिजली की उपलब्धता गत वर्ष के मुकाबले 6.80 प्रतिशत अधिक रही।

25. राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को कुल उपलब्ध बिजली का 50 प्रतिशत सस्ती दरों पर मुहैया कराने के लिये वचनबद्ध है। इसलिये राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 125 करोड़ रुपये नकद एवं 100 करोड़ रुपये समायोजन के रूप में बतौर ग्रामीण बिजलीकरण सबसिडी के तौर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को बिजली की रियायती बिक्री की पूर्ति करने के लिए चालू वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान समायोजन द्वारा 423.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ग्रामीण बिजलीकरण सबसिडी दी गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 150 करोड़ रुपये की नकद ग्रामीण बिजलीकरण सबसिडी देने और 100 करोड़ रुपये का समायोजन करने का प्रस्ताव रखा है।

26. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड राज्य में नये बिजली उत्पादन संयन्त्र लगाने का प्रयास कर रहा है ताकि बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। अल्पकालिक उपाय के रूप में बोर्ड ने बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। इन परियोजनाओं में तरल ईंधन आधारित बिजली परियोजना (41x25मैगावाट), पानीपत थर्मल विस्तार यूनिट-6 (210 मैगावाट) और पानीपत थर्मल यूनिट 1–4 (440 मैगावाट) का नवीकरण और इसका आधुनिकीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक बिजली खरीद संविदाओं के लिए केन्द्रीय/निजी ऐजेंसियों के साथ बातचीत की गई है। इसमें एन०टी०पी०सी० की फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना (400 मैगावाट) मैसर्ज इंडियन ऑयल

[श्री चरण दास]

कॉर्पोरेशन, पानीपत की तरल ईंधन आधारित बिजली परियोजना (240 मैगावाट) और मैसर्ज कंसोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पॉवर ऐशिया की उड़ीसा आधारित बिजली परियोजना (500 मैगावाट) शामिल है दीर्घावधि आधार पर यमुनानगर (1000 मैगावाट), हिसार (500 मैगावाट) और भिवानी (500 मैगावाट) में नई ताप बिजली परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी। राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी से 2051 मैगावाट वाली पार्वती पन बिजली परियोजना की संयुक्त जांच करने और इसकी क्रियान्विति के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ एक समझौता किया है। पड़ौसी राज्यों और यहां तक कि पड़ौसी देश नेपाल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए विचार विमर्श भी किया जा रहा है।

27. बिजली क्षेत्र के लिए योजनागत परिव्यय वर्ष 1996-97 का 261.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1997-98 के लिए 287.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

28. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सुधारीकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। बिजली क्षेत्र को कार्य की दृष्टि से विभिन्न कम्पनियों में बांट दिया जायेगा जोकि बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के कार्य की देखरेख करेंगी। एक स्वतंत्र राज्य बिजली नियामक आयोग स्थापित किया जायेगा, जो बिजली टैरिफ को नियमित करेगा और विभिन्न कम्पनियों के कार्य की देख-रेख करेगा। राज्य में पारेशन व वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अगले छः वर्षों के दौरान 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परिव्यय से एक निवेश योजना बनाने हेतु विश्व बैंक के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

29. बिजली की बिक्री से होने वाला कुल राजस्व वर्ष 1995-96 के दौरान 1160.95 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 1996-97 के दौरान बढ़कर 1477.63 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

30. राज्य सरकार ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोतों को भी बढ़ावा दे रही है जिसके अन्तर्गत वर्ष, 1997-98 में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय योजनाओं पर 3.80 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

सड़क संरचना

31. सुविकसित और समुचित सड़क संरचना राज्य के समुचे विकास के लिये आवश्यक है। चालू वर्ष के दौरान जनवरी, 1997 तक 74 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया एवं 213 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा तथा सुदृढ़ किया गया है। वर्ष के दौरान 1302 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर नई परत बिछाई गई है। नई सड़कों के निर्माण और वर्तमान सड़कों को सुधारने/सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1996-97 के लिए 28 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

32. बढ़ते हुए यातायात के मद्देनजर राज्य सरकार ने राजमार्गों की 871 किलोमीटर की लम्बाई को सुधारने के लिए विश्व बैंक से 961.48 करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध किया है। इस परियोजना का सम्भावना अध्ययन पूरा हो चुका है। इस परियोजना के लिए 9 वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 1997-98 में समुचित प्रावधान किया गया है।

33. विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भवन तथा सड़क विभाग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्तर्गत 1130 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा जा रहा है। 9वीं योजना अवधि के दौरान 450 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण और 2800 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों को चौड़ा तथा सुदृढ़ करके सुधारने का प्रस्ताव है।

11.00 बजे 34. इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997-98 के लिए 108.90 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें 80 करोड़ रुपये हरियाणा राज मार्ग सुधार परियोजना, 28.90 करोड़ रुपये 90 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण और 450 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों के सुधार के लिए शामिल हैं।

35. राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-1 को चारमार्गी बनाने के कार्य में प्रयास प्रगति हुई है। मुरथल से समालखा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को चारमार्गी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है और समालखा से करनाल तक का भाग दिसम्बर 1997 तक पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-1 के करनाल से अम्बाला तक के हिस्से को चारमार्गी बनाने का कार्य चल रहा है और इसके जून, 1998 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच 56 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-2 को चारमार्गी बनाने का कार्य चल रहा है और इसके अगस्त, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

36. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बाईपास भी मुकम्मल किये गये हैं। राज्य राजमार्ग कैथल और डोभ पर बाईपास पहले ही पूरे हो चुके हैं। 20.06 करोड़ रुपये की लागत से हिसार, ढाण्ड, जीन्द, सोनीपत और झज्जर के बाइपासों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। ढाण्ड और झज्जर के बाइपासों का निर्माण कार्य जारी है।

37. राज्य ने 63.61 किलोमीटर योजक सड़कों के निर्माण, 216 किलोमीटर लम्बी सड़कों को सुधारने और 5 नये पुलों के निर्माण के लिए 15.35 करोड़ रुपये की राशि देने हेतु राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के समक्ष भी प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य को वर्ष 1997-98 के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है।

38. वर्ष 1996-97 में 27.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 9 पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान 23.94 करोड़ रुपये की राशि से 9 नये पुल बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। दिसम्बर, 1996 तक पहले ही चार पुलों को पूरा किया जा चुका है और चालू वित्त वर्ष के दौरान चार और पुलों को पुरा किये जाने की सम्भावना है।

सिंचाई

39. कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये सिंचाई की एक अहम भूमिका है। अतः राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है। पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना नहर का निर्माण वर्तमान सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य सरकार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार पर लगातार दबाव डाल रही है। विदशतावश हरियाणा को पंजाब सरकार तथा भारत सरकार को निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने हेतु निर्देश जारी करने के लिये उच्चतम न्यायालय की शरण में जाना पड़ा है।

40. पूर्व योजनाओं के सफल निष्पादन से प्रभावित होकर विश्व बैंक ने हरियाणा में जल संसाधन समेकन परियोजना के लिये वित्तीय सहायता दी है। भारत में अपनी किस्म की यह एक पहली योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य पुराने निर्माणों का सुधार, नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण तथा क्षारीय क्षेत्रों के लिये भूमिगत जलनिकास प्रणाली को तैयार करना है। जल संसाधन समेकन परियोजना, जिस पर 1858 करोड़ रुपये खर्च होना है, 6 वर्षों में पूरी होगी तथा इसमें 975 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता विश्व बैंक से प्राप्त होगी। इसके लिये वार्षिक योजना 1997-98 में 293.90 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

[श्री चरण दास]

41. जल संसाधन समेकन परियोजना के अन्तर्गत 240.67 करोड़ रुपये की लागत से एक जल प्रबन्ध सुधार योजना को लागू करने का प्रस्ताव है जिससे नहरों के अंतिम छोर तक खेतों को पानी पहुंचाया जा सकेगा। वर्ष 1997-98 के दौरान इस परियोजना पर 50.11 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव है।

42. माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हथनीकुण्ड बैराज पर, जल संसाधन समेकन परियोजना के अन्तर्गत अक्तूबर, 1996 में कार्य आरम्भ हो चुका है। इस परियोजना पर कार्य 219.19 करोड़ रुपये की लागत से, तीन वर्षों के अन्दर अर्थात सितम्बर, 1999 तक पूरा हो जायेगा।

43. राज्य सरकार ने भाखड़ा मुख्य नहर तथा नरवाना शाखा की क्षमता को बहाल करने का प्रयास किया है जिसकी क्षमता, 1954 से लगातार चलने के कारण 10700 क्यूसेक से कम होकर 9100 क्यूसेक रह गई थी। इस कार्य हेतु वर्ष 1996-97 में 5.21 करोड़ रुपये का उपबन्ध है, जिसमें से वर्ष के दौरान पंजाब सरकार को 2.50 करोड़ रुपये दे दिये गये हैं। यह अनुमान है कि जून, 1998 तक इन सभी जल-मार्गों की पूरी क्षमता बहाल हो जायेगी। इससे हरियाणा राज्य को 1000 क्यूसेक जल का लाभ होगा।

44. भाखड़ा तथा पश्चिमी यमुना नहर के कमांड क्षेत्रों में सिंचाई के सुधार के लिये कई स्कीमें एक दशक से निर्माण के लिये लम्बित पड़ी थीं। राज्य सरकार की अब इन स्कीमों को पूरा करने की योजना है। इस कार्य के लिये नाबार्ड को 61 करोड़ रुपये की एक परियोजना पेश की गई थी, जिसे आर०आई०डी०एफ०II स्कीम के अन्तर्गत मंजूर कर दिया गया है और इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 20 स्कीमों पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

45. राज्य में नहरों के नेटवर्क, जिसमें लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, की स्थिति खराब हुई है और इस प्रणाली की वहन क्षमता में पर्याप्त रूप से कमी आई है। यदि जलमार्गों की मुरम्मत तथा रिमॉडलिंग नहीं की गई तो ये क्षमता और भी कम हो जायेगी। इस जरूरत के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 1996-97 में समाप्त होने वाली आठवीं योजना के दौरान इन स्कीमों पर 43.20 करोड़ रुपये का खर्च करने की प्रत्याशा है जिस में से वर्ष 1996-97 में इन परियोजनाओं पर 17.40 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है।

46. सिंचाई विभाग जल निकासी एवं बाढ़ों की समस्या से जुझने के लिए सक्षम प्रयास कर रहा है। हरियाणा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों रिंग बांधों के निर्माण, बाढ़ पम्पो की व्यवस्था तथा अन्य रोकथाम उपायों को कार्यरूप देने के लिये वर्ष 1997-98 में 48.70 करोड़ रुपये की स्कीमों को स्वीकृत किया है ताकि वर्ष 1995 के दौरान बाढ़ से हुई हानि की पुनरावृति को रोका जा सके।

47. हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम ने उपलब्ध जल संसाधनों को निहायत किफायत से इस्तेमाल के लिये कच्चे जल-मार्गों को पक्का करने का कार्य आरम्भ किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 12.89 लाख फुट लम्बे (391 किलोमीटर) कच्चे जलमार्गों को पक्का किया जा चुका है जिससे 2820 हैक्टेयर भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 1997-98 के दौरान 41.50 लाख फुट लम्बे कच्चे जलमार्गों को पक्का करने का लक्ष्य बनाया गया है जिससे 8750 हैक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध होगी।

48. वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने 900 करोड़ रुपये की लागत से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को आरम्भ किया है जिससे वर्तमान में चालू मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी की जाएंगी जो फन्ड्स् के अभाव के कारण लटक रहीं थी। चालू वर्ष के दौरान 45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और वर्ष 1997-98 के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

49. वार्षिक योजना 1997-98 में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये 329.69 करोड़ रुपये, बाढ़ नियन्त्रण हेतु 12.10 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई के लिये 6071 करोड़ रुपये तथा कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण के लिये 15 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

कृषि

50. राज्य की अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि क्षेत्र में नवीनतम फार्म टैक्नोलोजी के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप ही कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। हमारी सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान किसानों को 3.89 लाख क्विंटल अधिक उपज वाले प्रमाणित बीज वितरित किये गये हैं, जबकि 1995-96 के दौरान 2.90 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया गया था। राज्य में किसानों को वितरित किये गये प्रमाणित बीजों की यह मात्रा सबसे अधिक है। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों की 7.74 लाख टन की रिकार्ड खपत हुई है जबकि 1995-96 के दौरान यह मात्रा 7.24 लाख टन थी। खरीफ फसल, 1996 में 33.14 लाख टन का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है इसमें 25.02 लाख टन चावल का उत्पादन भी शामिल है, जो सबसे अधिक है। इसी प्रकार 1995-96 के मुकाबले इस रबी मौसम में 97,000 हैक्टेयर अधिक क्षेत्र रबी फसल के अन्तर्गत लाया गया है। आशा है कि इस वर्ष 50,000 हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 70,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की काश्त की जायेगी।

51. वर्ष के दौरान राज्य में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है जो वर्ष 1996-97 के खरीफ और रबी के 112.90 लाख टन के संयुक्त लक्ष्य से भी ज्यादा होगा। कृषि विभाग चालू वर्ष में फॉसफेटिक उर्वरकों पर 100 करोड़ रुपये की सबसिडी देगा जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान विभाग द्वारा केवल 20 करोड़ रुपये की सबसिडी दी गई थी।

52. उपलब्ध जल संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए फव्वारा यंत्र लगाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के 2154 फव्वारा यंत्रों के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान 6500 यंत्र लगाने का लक्ष्य है।

53. धान, सूरजमुखी और सब्जियों के हाईब्रिड किस्मों के बीज विकसित करने को भी प्राथमिकता दी गयी है। पटौदी और पलवल में "सीड प्रोसेसिंग प्लांट" लगाये जा रहे हैं। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने, मानव संसाधन विकसित करने एवं कुशलता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक से 53.74 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की गई है। टिशू कल्चर तकनीक अपनाने पर भी बल दिया जा रहा है।

54. चूंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है अतः आधुनिक भंडारण सुविधाएं जुटाना भी राज्य सरकार के लिए जरूरी हो गया है। हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम द्वारा रिवाड़ी में इनलैंड कंटेनर डिपो तथा कंटेनर फ्रेट केन्द्र की स्थापना की जा रही है ताकि आयात और निर्यातकर्ताओं को भंडारण तथा ड्राई

[श्री चरण दास]

पोर्ट सुविधाएं दी जा सकें। भारत सरकार के सहयोग से पलवल में कंटेनर फ्रेट केन्द्र और गुड़गांव में सेटेलाइट फ्रेट सिटी भी बनाने का प्रस्ताव है। सेटेलाइट फ्रेट सिटी में सीमा शुल्क भुगतान सहित एयर-कार्गो के लेन-देन की व्यवस्था भी होगी।

बागवानी

55. बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अधिक अवसर जुटाने तथा पोषण की किस्म एवं पर्यावरण में सुधार लाने के लिये बागबानी के विकास पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। फूलों और खुम्भी के विकास तथा ड्रिप सिंचाई और पॉलीग्रीन हाउस जैसी नयी तकनीकों को अपनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब्जियों तथा फलों का उत्पादन वर्ष 1996-97 में क्रमशः 14.50 लाख टन और 1.45 लाख टन तक बढ़ गया है। फूलों की खेती के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र वर्ष 1990-91 में 50 हैक्टेयर था जो बढ़कर वर्ष 1996-97 में 1800 हैक्टेयर हो गया है। खुम्भी का उत्पादन, वर्ष 1990-91 में 850 टन था जो वर्ष 1996-97 में बढ़कर 2500 टन हो जाने की सम्भावना है।

56. सिंचाई जल के उत्तम ढंग से संरक्षण, परिरक्षण एवं उपयोग हेतु 1300 हैक्टेयर भूमि को ड्रिप और माइक्रो सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है, इससे सिंचाई जल की क्षमता तीन से चार गुणा बढ़ जायेगी। उत्तम तथा बीमारी-रहित नर्सरी और बेमौसमी उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के किसानों में ग्रीन हाउस तकनीक को लोकप्रिय बनाया गया है और अब तक राज्य में 102 ग्रीन हाउस स्थापित किये जा चुके हैं। बागवानी के विकास के लिये वर्ष 1997-98 की योजना में 4.43 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है।

57. वर्ष 1997-98 के दौरान विभाग का प्रस्तावित लक्ष्य एक लाख हैक्टेयर भूमि में 15 लाख टन सब्जियों का उत्पादन, 2700 टन खुम्बी उत्पादन, 2000 हैक्टेयर भूमि को फूलों की काश्त के अन्तर्गत लाया जाना और 23600 हैक्टेयर भूमि पर 1.75 लाख टन फलों का उत्पादन करना होगा।

पशुधन विकास

58. पशुधन विकास हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। राज्य में वर्ष 1992 की पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या 98.97 लाख हो गई है और 620 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध होने के कारण हरियाणा राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य का पशु पालन विभाग अपने 546 पशु अस्पतालों, 859 पशु डिस्पैंसरियों, 60 कृत्रिम वीर्य सेचन केन्द्रों और 751 स्टॉकमेन केन्द्रों के व्यापक नेटवर्क के ज़रिए नस्ल सुधार सन्तुलित भोजन और प्रभावी स्वास्थ्य रक्षा जैसी विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से पशुधन सुधार में लगा हुआ है। वर्ष 1997-98 के दौरान 20 नए पशु अस्पताल खोलने व 80 डिस्पैंसरियों और स्टॉकमेन केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार से 3.49 करोड़ रुपये की सहायता द्वारा हरियाणा नस्ल की गायों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए राज्य में राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

59. राज्य में पशुपालन और डेरी विकास के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 10.62 करोड़ रुपये के परिव्यय से 40.82 लाख मिलियन टन दूध, 6369 लाख अण्डे और 18.73 लाख किलोग्राम ऊन उत्पादन करने का प्रस्ताव है।

60. राज्य में नीली क्रांति भी आ रही है। मछलियों के विपणन की सुविधा जुटाने के लिए फरीदाबाद में एक फिश मार्किट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पानीपत में एक दूसरी मार्किट के 31 मार्च, 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वर्ष 1996-97 के दौरान 1000 लाख मछली का बीज तालाबों में डालने और 30,000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य वर्ष 1997-98 में बढ़कर 1400 लाख मछली बीज और 32,000 टन मछली उत्पादन तक हो जाएगा। इसके लिए वर्ष 1997-98 में 4.11 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

सहकारिता तथा ऋण

61. माननीय सदस्यों को यह मालूम ही है कि सहकारिता आन्दोलन ने किसानों की भागीदारी से कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों के विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न राज्य सहकारिता संस्थाएं किसानों और ग्रामीण कारीगरों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

62. चालू वित्त वर्ष के दौरान, 31 दिसम्बर, 1996 तक राज्य में सहकारी संस्थाओं द्वारा 935.45 करोड़ रुपये के कृषि और 25 करोड़ रुपये के गैर कृषि ऋण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान, कृषि सम्बन्धी विकास के लिये 91.22 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन कर्ज़े भी दिये गये हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1.41 करोड़ रुपये के अल्पावधि कर्ज़ों को मध्यावधि कर्ज़ों में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी ऋण पद्धति को विकसित करने और किसानों को प्रयाप्त ऋण देने के लिये किसानों की अधिकतम उधार सीमा को 30,500 रुपये से बढा कर 40,000 रुपये कर दिया गया है। किसानों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिये सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विभिन्न नई स्कीमें शुरू की गई हैं।

63. सहकारिता क्षेत्र के लिये वर्षिक योजना 1997-98 में 621 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

उद्योग

64. हरियाणा ने देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय तरक्की की है। भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण तथा डी-लायसेंसिंग नीति से उपलब्ध अवसरों का भी हरियाणा राज्य ने पूरा लाभ उठाया है। औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के लिए हरियाणा में अब तक कुल 1741 औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापन फाइल किये गये हैं जिनसे 17637 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश होगा। इनमें से 692 औद्योगिक उद्यमकर्त्ता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और 223 प्रोजैक्ट कार्यान्वित होने की स्थिति में हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान नये निवेशों को आमन्त्रित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा की गई विशेष प्रेरणा के परिणामस्वरूप 110 औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन फाईल किये गये हैं जिनमें 626.47 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। इसी प्रकार चालू वर्ष में 168.99 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। इसी प्राकर चालू वर्ष में 168.99 करोड़ रुपये के निवेश से 21 बड़े तथा मंझले उद्योग तथा लघु पैमाने के उद्योग स्थापित हुए हैं।

65. शिक्षित एवं बेरोज़गार युवाओं को औद्योगिक वित्त उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत अब तक 3693 लाभार्थियों को ऋण सहायता प्रदान की गई है।

66. राज्य सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में नई औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है। एकीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र, भिवानी, हौज़री केन्द्र, गन्नौर, उद्योग विहार, चरण-7 गुड़गांव और औद्योगिक सम्पदा, पलवल जैसी नई परियोजनाओं पर कार्य होना है।

[श्री चरण दास]

67. वर्ष 1997-98 के दौरान 50 बड़े व मध्यम यूनिट तथा 5000 लघु पैमाने के ग्रामीण औद्योगिक यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत 7200 लाभार्थियों को लाभ देने की योजना है।

68. हमारी सरकार इलैक्ट्रानिकी विकास को भी बढ़ावा दे रही है। इस कार्य के लिए गुड़गांव में 40 एकड़ भूमि पर एक इलैक्ट्रॉनिक नगर विकसित किया गया, जिससे हाई टैक्नोलॉजी तथा निर्यातोन्मुखी इलैक्ट्रानिक्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है जिससे सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाली इकाइयों को लाभ होगा तथा 50 एकड़ क्षेत्र में एक इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टैक्नालोजी पार्क स्थापित किया गया है जिससे हार्डवेयर के निर्यात को लाभ होगा। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में इलैक्ट्रॉनिक क्रान्ति लाना है।

औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं

69. उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक वित्त की सहज प्राप्ति बहुत जरूरी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य में औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वर्ष 1996-97 के दौरान निगम ने संयुक्त/सहायता प्राप्त परियोजनाओं में इक्विटी पूँजी के रूप में 189.50 लाख रुपये की राशि का निवेश किया। चालू वित्त वर्ष के दौरान निगम द्वारा 100 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर करने की संभावना है एवं 60 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करने का अनुमान है।

70. हरियाणा वित्त निगम द्वारा वर्ष के दौरान 155 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने का अनुमान है, जिसमें से 140 करोड़ रुपये के ऋण वास्तव में वितरित किए जाएंगे।

संस्थागत वित्त और ऋण नियन्त्रण

71. संस्थागत वित्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2515 करोड़ रुपये की है, जो गत वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से 26 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1996-97 में गत वर्ष की तुलना में कृषि व इससे सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये लक्ष्य 24 प्रतिशत, लघु उद्योगों के लिये 22 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र के लिये 52 प्रतिशत अधिक है। राज्य में ऋण वितरण की वर्तमान गति को देखते हुये, चालू वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि होने की सम्भावना है।

पर्यटन

72. हरियाणा राज्य को अपने खूबसूरत दृश्यों एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से सज्जित पर्यटन केन्द्रों पर गर्व है जो प्रतिवर्ष 72 लाख पर्यटकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हरियाणा पर्यटन की गणना देश के सर्वोत्तम पर्यटनों में की जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्य की बागडोर संभालने के उपरान्त राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की पुनर्स्थापना की, ताकि पर्यटन उद्योग को नया जीवन दिया जा सके।

73. अनेक सुन्दर एवं प्रतिष्ठित पर्यटन परियोजनाएं, जैसे पानीपत तथा जीन्द में बैन्क्वट हाल, पिपली में फास्ट फूड केन्द्र, मनसा देवी व पेहोवा में यात्रिका तथा राई में एथनिक इण्डिया परियोजना, चालू वर्ष के दौरान तथा आगामी वित्त वर्ष में मुकम्मल करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं

के अतिरिक्त भिवानी और हांसी में नए पर्यटन केन्द्र, तिलीयर पर्यटन कम्पलैक्स रोहतक में फास्ट फूड केन्द्र, ओयसिस, करनाल में मिनी गोल्फ कोर्स व मिनी चिड़ियाघर और नया फास्ट फूड केन्द्र, हिसार, हिसार में फास्ट फूड केन्द्र एवं गुड़गांव पर्यटन केन्द्र के विस्तार की योजना है।

74. विभाग ने प्राइवेट उद्यमकर्ताओं को अपने पर्यटन उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है और लगभग 351 करोड़ रुपये के निवेश वाली 48 पर्यटन परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। वर्तमान पर्यटन नेटवर्क के विस्तार और नये पर्यटन केन्द्र विकसित करने के लिए वर्ष 1997-98 में 403 लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

परिवहन

75. यात्रियों को परिवहन सुविधाएं जुटाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। हरियाणा राज्य परिवहन के 19 डिपों और 18 सब-डिपों में 3894 बसें हैं जो लगभग 1800 रूटों पर चल रही हैं और ये बसें प्रतिदिन लगभग 17.52 लाख यात्रियों को लगभग 11.63 लाख किलोमीटर यात्रा कराती हैं। विभाग ने यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए अब तक 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक बस स्टैंड स्थापित किये हैं। जुलाना, असंध, समालखा, अटेली, रतिया और राजौंद में निर्माण कार्य चल रहा है। रोहतक बाइपास, अम्बाला छावनी, डाण्ड और हथीन में बस स्टैंड के लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और इन पर भविष्य में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। बस स्टैंड के निर्माण के लिए लोहारू, भिवानी, कलायत और कालाँवाली में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू की गई है।

76. राज्य सरकार ने ग्रामीण युवकों को रोज़गार सुविधाएं देने एवं अनधिकृत तौर पर चलने वाले वाहनों से होने वाली राजस्व हानि को रोकने के लिए मैक्सी कैब/मारुति/एमबैसेडर टैक्सियों को नियमित करने की नीति की घोषणा की है।

77. वर्ष 1997-98 के दौरान 567 पुरानी बसों को बदलने के लिए 4275 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण विकास

78. राज्य सरकार ने रोज़गार सुविधाएं जुटाकर और बेहतर सामाजिक व आर्थिक परिवेश के माध्यम से ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किये हैं।

79. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 937.16 लाख रुपये की राशि में से जनवरी, 1997 के अन्त तक 908.68 लाख रुपये की राशि 13566 लाभार्थियों को सहायता के रूप में दी गई है। वार्षिक योजना 1997-98 के लिए 1047 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव है। विभिन्न स्व-रोज़गार कार्यों में ग्रामीण युवकों का कौशल बढ़ाने के लिए राज्य में ट्राइसेम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 2449 ग्रामीण युवकों को जनवरी, 1997 तक विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया।

80. सूखे की रोकथाम एवं पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा मरुस्थल विकास कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिसको वाटरशैड विकास तकनीक के अनुसार लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए भू एवं नमी संरक्षण, भूमि को समतल बना कर उसे उपज

[श्री चरण दास]

के योग्य बनाना, जल संसाधनों का विकास करना, वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास इत्यादि कार्यक्रम शामिल हैं। यह कार्यक्रम छः ज़िलों में चलाया जा रहा है तथा इस पर वर्ष 1997-98 में 649 लाख रुपये का खर्च करने का प्रस्ताव है।

81. बेरोज़गार और कम आय वाले ग्रामीण लोगों को लाभदायक रोज़गार जुटाने के लिये 80:20 के हिस्सा आधार पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता से जवाहर रोज़गार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनवरी, 1997 तक 9.84 लाख श्रम दिवस जुटाए गए। इस कार्यक्रम के लिये वार्षिक योजना 1997-98 में 800 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

82. राज्य के 77 ब्लाकों में उस समय, जब कृषि क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध नहीं होते लाभदायक रोज़गार जुटाने के दृष्टिगत रोज़गार आश्वासन योजना चलाई गई है। शेष ब्लाकों को वर्ष 1997-98 के दौरान इसके अन्तर्गत लाने की सम्भावना है। जनवरी 1997 के अन्त तक विभिन्न ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरणों को 3661.50 लाख रुपया उपलब्ध करवाया जा चुका है तथा अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 17.17 लाख श्रम दिवस जुटाए जा चुके हैं।

83. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए जल स्त्रोतों की व्यवस्था करने हेतु फरवरी, 1997 से गंगा कल्याण योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर एवं ग्रुपों में बोरवैल एवं ट्यूबवैल के लिये आर्थिक सहायता दी जाएगी। व्यक्तिगत लाभार्थियों को 12,500 रुपये तथा ग्रुप लाभार्थियों को 40,000 रुपये की अधिकतम आर्थिक सहायता दी जाएगी।

84. इस स्कीम में चालू वर्ष के लिये 75 लाख रुपये और वर्ष 1997-98 के लिये 250 लाख रुपये का उपबन्ध है।

वन

85. तेज़ गति से हो रहे उद्योगीकरण एवं वनों के धीरे-धीरे नष्ट होने के कारण वृक्षारोपण तथा पर्यावरण संतुलन अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसलिये राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिये तथा पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिये विभिन्न वृक्षारोपण के कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। इन कार्यक्रमों का एक उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी है।

86. वन विभाग द्वारा एक नई योजना हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना, यूरोपियन संघ की सहायता से कार्यान्वित करने की योजना तैयार की गई है जिस पर अगले 9 वर्षों में 126 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। इस परियोजना को यूरोपियन संघ द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा चालू वर्ष में इसका वित्तीय समझौता हो गया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग वृक्षारोपण की कई अन्य योजनाओं पर वर्ष 1996-97 में 34.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रहा है। वर्ष 1997-98 में 35.77 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है तथा 33 लाख श्रम दिवस जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी विकास

87. राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दे रही है। हरियाणा शहरी

विकास प्राधिकरण, राज्य की एक मुख्य शहरी विकास एजेन्सी है, जो शहरों के एकीकृत विकास में जुटी हुई है।

88. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली के आस-पास के सेटलाइट नगरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु वर्ष 1996-97 में 8 करोड़ रुपये और वर्ष 1997-98 में 10 करोड़ रुपये के अनुदान देने के प्रस्ताव हैं। इस प्रयोजनार्थ कई विकासकारी परियोजनाएं अनुमोदनार्थ भारत सरकार को प्रस्तुत की गई हैं।

89. स्थानीय निकाय भी शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाएं और नागरिक सेवाएं जुटा रहा है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन के बकायों का भुगतान करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी है। राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है जो स्थानीय निकायों को अपने अतिरिक्त स्त्रोत बढ़ाने संबन्धी उपायों का सुझाव देगा। इसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। 10वें वित्त आयोग ने 1996-2000 की अवधि के लिये 16.58 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है, जिसमें 4.15 करोड़ रुपये वर्ष 1997-98 के लिए हैं।

90. शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरण सम्बन्धी सुधार, आई०डी०एस०एम०टी० स्कीम के अन्तर्गत लघु तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास जैसी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत, 82 नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना में 630 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत हिसार, रोहतक, कलानौर, गुड़गांव, बरवाला और चरखी-दादरी जैसे नगरों को बड़े शहरों पर पड़ने वाले दबाव को रोकने के लिए चुना गया है। शहरी क्षेत्रों के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजनार्थ वार्षिक योजना 1997-98 में 18.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है,जिसमें 10 करोड़ रुपये दिल्ली के आस-पास के सेटलाइट नगरों के विकास के लिए, 3.65 करोड़ रुपये शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये और 4.15 करोड़ रुपये नगरपालिकाओं की सहायता के लिए शामिल हैं।

पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

91. राज्य सरकार ने विशेष कार्यक्रमों द्वारा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। राज्य के सबसे अधिक पिछड़े दो क्षेत्रों मेवात तथा शिवालिक की ओर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। मेवात क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य पेयजल, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, संचार व शिक्षा के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं एवं मूलभूत सुविधाएं जुटाना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

92. मेवात क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से मेवात क्षेत्र विकास परियोजना नामक एक नई परियोजना चलाई जा रही है। मेवात के लोगों का सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने हेतु इस सात वर्षीय परियोजना के अन्तर्गत 70 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। अगली योजना 1997-98 में मेवात कैनाल के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है जिस पर अगले वर्ष में 30 करोड़ रुपया खर्च होने की संभावना है। वर्ष 1997-98 में विभिन्न विकास कार्यों पर इस क्षेत्र के लिए 16.62 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

[श्री चरण दास]

93. अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला ज़िलों के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए शिवालिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के संरक्षण में इस बोर्ड ने विकास की गति और तेज़ कर दी है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस क्षेत्र के विकास पर 475 करोड़ रुपये का प्रावधान है एवं वर्ष 1997-98 के लिए 523 लाख रुपये का प्रस्ताव है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यों के लिए 31.30 करोड़ रुपये का उपबन्ध करने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न विभागों के सामान्य परिव्यय के अतिरिक्त है।

रोज़गार

94. सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित युवाओं को पर्याप्त रोज़गार के साधन जुटाना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

95. रोज़गार विभाग द्वारा कुशल एवं अर्ध-कुशल युवाओं को स्व-रोज़गार के लिए स्टाइपेण्ड देने एवं रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोज़गार युवकों को बेरोज़गारी भत्ता देने की योजना चलाई गई है। विभाग ने 10+2 व्यावसायिक परीक्षा पास तथा डिप्लोमा धारक आवेदकों को रोज़गार मुहैया करवाने के लिए एक स्कीम, कुशल तथा अर्ध-कुशल बेरोज़गार युवकों के लिए शुरू की है ताकि आवेदकों को प्रशिक्षण के बाद लाभपूर्ण रोज़गार में समायोजित किया जा सके। वर्ष 1996-97 के दौरान 728 आवेदकों को 24 लाख रुपये की राशि वितरित करने का अनुमान है। चालू वर्ष के दौरान विभाग ने 12648 आवेदकों को लाभकारी रोज़गार दिलवाया है जिनमें से 8227 को विभाग के विशेष प्रयत्नों से निजी क्षेत्र में रोज़गार मिला है। बेरोज़गारी भत्ते का वितरण स्कीम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 16236 आवेदकों को 65 लाख रुपये का भत्ता वितरित किया गया है।

96. बेरोज़गार युवकों को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने एवं रोज़गार कार्यालयों के कार्यों में निपुणता लाने के लिये विभाग, रोज़गार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण करने की ओर अग्रसर है। राज्य में 9 कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिए अब तक 30.19 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

शिक्षा

97. सामाजिक प्रगति के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं अनिवार्य हैं। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने, पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों की दर 10 प्रतिशत तक कम करने और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कैथल, जीन्द, हिसार और सिरसा में शुरू किया गया है। चालू वर्ष के दौरान तीन और ज़िलों में अर्थात् गुड़गांव, भिवानी और महेन्द्रगढ़ में यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा का और विस्तार करने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो 1995-96 में राज्य के 44 खण्डों में लागू था, अब 88 खण्डों में लागू कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान 11.31 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ है जबकि 1995-96 में 5.92 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला था।

98. अल्पसंख्यक समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंजाबी को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है। पंजाबी साहित्य तथा पंजाबी भाषा के विकास के उद्देश्य से पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन किया गया है।

99. राज्य सरकार समय-समय पर नये कॉलेज खोलकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। राज्य में 148 कॉलेजों के अतिरिक्त 2 नए कॉलेज 1997-98 में खोलने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार में 670 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देकर इस महाविद्यालय में 10 नए तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने में सहायता की है।

100. वर्ष 1997-98 में शिक्षा के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 70.20 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है।

101. राज्य सरकार ने औद्योगिक एवं अन्य संस्थाओं के लिए मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए तकनीकी संस्थाओं का बेहतर नेटवर्क मुहैया किया है। तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम में विश्व बैंक सहायता प्राप्त द्वितीय तकनीकी शिक्षा परियोजना एक मुख्य परियोजना है जिसको 121 करोड़ रुपये की लागत से तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सुधार लाने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग भी 15104 विद्यार्थियों को 72 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहा है, जिसके लिए वार्षिक योजना 1997-98 में 4.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य

102. लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना हमारी सरकार का एक अहम वायदा है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को तेज करने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य संघ नामक एक योजना चलाई गई है जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं प्रतिरक्षण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

103. हरियाणा ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों की तकनीक अपना कर प्लस पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक ढंग से लागू किया है। 7 दिसम्बर, 1996 एवं 18 जनवरी,1997 को आयोजित प्लस पोलियों अभियान में , 0-5 वर्ष के 27,84,638 बच्चों को मुंह द्वारा पोलियो टीके की दवाई दी गई जबकि लक्ष्य 26,68,240 बच्चों का था।

104. प्लस पोलियो कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर राज्य में 22 जुलाई से 27 जुलाई, 1996 तक प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों की जांच के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत राज्य के 16,123 विद्यालयों में लगभग 25 लाख प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की अलग-अलग बीमारियों के लिये जांच की गयी और किसी भी बीमारी से पीड़ित बच्चों को उचित अस्पतालों में भेजा गया। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के विचार से वर्ष 1996-97 के दौरान 9 और मोबाइल वैनों की खरीद की गई। इसके साथ-साथ 16 मोबाइल हैल्थ यूनिट और 2 मोबाइल डैंटल यूनिट भी चालू रहे।पं० भगवत दयाल मैडिकल साईंसिस पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीच्यूट रोहतक में अति विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करके वर्ष 1997-98 से इसका दर्जा बढ़ा दिया गया है। इस संस्थान में 3.75 करोड़ रुपये की लागत से ट्रॉउमा ब्लाक भी शुरू किया जायेगा। लगभग 2 करोड़ रुपये नये उपकरण खरीदने के लिये दिये जायेंगे और लगभग 2 करोड़ रुपये पुस्तकालय को वातानुकूलित बनाने, रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण आदि के लिये दिये जायेंगे। आगामी वर्ष के लिए संस्थान का वार्षिक बजट 10 करोड़ रुपये और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

[श्री चरण दास]

105. माननीय सदस्यों को याद ही होगा कि चालू वर्ष में राज्य में डेंगू बुखार और मलेरिया फैलने से बहुत नुकसान हुआ था जिसमें मेवात क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। राज्य प्रशासन ने इस संकट का सामना करने के लिए विशेष उपाय किये। ग्रामीण क्षेत्रों में बी०एच०सी/ मैलाथिन का छिड़काव किया गया, लार्वा समाप्त करने के लिए साप्ताहिक उपचार किये गये। प्रभावित गांवों में अस्थायी प्रयोगशालायें खोली गईं। विभाग के पास पहले से ही उपलब्ध 14 मशीनों के अतिरिक्त 160 धुआँ छोड़ने वाली मशीनें और 10 वाहन चालित धुआं छोड़ने वाली मशीनें काम पर लगा दी गयी । मैडिकल कालिज, रोहतक और बी०के० अस्पताल, फरीदाबाद में रक्त जांच के लिए ऑटोमैटिक ब्लड सैपेरेटर की व्यवस्था की गई। वर्ष के दौरान डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए 10.27 करोड़ रुपये की राशि स्वास्थ्य विभाग को खर्च हेतु दे दी गयी ।

106. राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 1996-97 के लिए 26.41 करोड़ रुपये और वार्षिक योजना 1997-98 के लिए 28.79 करोड़ रुपये का उपबन्ध, स्वास्थ्य विभाग के लिए किया है।

107. राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है तथा राज्य में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य नेटवर्क को सुदृढ़ करने के विचार से राज्य योजना वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत 2.05 करोड़ रुपये की राशि और वर्ष 1997-98 के लिए 1.85 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

जल सप्लाई और सफाई

108. राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेय जल सुविधाएं और उचित जल निकास व्यवस्था प्रदान करना है। हरियाणा देश के उन गौरवशाली राज्यों में से एक है जिसके सभी गांव तथा नगरों में पाइप जल सप्लाई की व्यवस्था की जा चुकी है।

109. चालू वर्ष 1996-97 के लिये 30.60 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के उन 550 गांवों में जल सप्लाई को सुधारने का लक्ष्य था जिनमें प्रति व्यक्ति जल सप्लाई कम थी। उनमें से 380 गांवों में 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त जल स्त्रोतों की व्यवस्था की गई है। आशा की जाती है कि लक्ष्य चालू वर्ष के अन्त तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

110. वर्ष 1997-98 के लिये 650 गांवों में जल सप्लाई 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए राज्य योजना में 28 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस परियोजना के लिये भारत सरकार से 14 करोड़ रुपये की राशि प्रत्याशित है।

111. 5000 से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के 405 गांव, जिनमें राज्य सरकार ने 110 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल सप्लाई को बढ़ाने की एक स्कीम शुरू की है, में सीवरेज निर्माण भी आवश्यक होगा। इससे ये गांव छोटे म्यूनिसिपल टाउनस् के बराबर हो जायेंगे।

112. चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 नगरों की जल सप्लाई के आवर्धन कार्य के लिये 10.20 करोड़ रुपये का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त 4.10 करोड़ रुपये की लागत से 5 नगरों में सीवरेज निर्माण कार्य शुरू किये जाने का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार ने 75:25 हिस्सा आधार पर फलोरीसिस कार्यक्रम के अन्तर्गत महेन्द्रगढ़ जिला में 64 गांवों के लिये 6.64 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना हाल ही में अनुमोदित की गई है।

113. ग्रामीण क्षेत्रों में मल शोधन सुविधाओं को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार की सहायता से 6 महत्वपूर्ण नगरों जैसे यमुनानगर, गुड़गांव, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद को इसके अन्तर्गत लाने के लिये यमुना कार्य योजना के अधीन एक मुख्य परियोजना शुरू की है जिन पर कार्य जोर शोर से शुरू हो गया है ताकि वर्ष के अन्त तक इस कार्य को पूरा किया जा सके। इस परियोजना पर कुल 211.56 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 20.64 करोड़ रुपये की लागत से 6 और नगरों जैसे छछरौली, इन्दरी, रादौर, पलवल, गोहाना और घरौंडा, जहां मल शोधन संयन्त्रों की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है, अनुमोदित किये गए हैं।

समाज कल्याण

114. राज्य सरकार ने वृद्धों, महिलाओं व बच्चों, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों, विमुक्त जातियों और पिछड़े वर्गों के समूचे विकास को उचित महत्त्व दिया है तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को उठाने के लिये एकीकृत पद्धति के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।

115. माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग लोगों को प्रतिमास की 7 तारीख तक पेंशन देने का वायदा किया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को पिछली सरकार के बाकायों का निपटान ही नहीं किया बल्कि हम प्रत्येक मास की 7 तारीख तक पेंशन का भुगतान भी सुनिश्चित कर रहे हैं।

116. महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए राज्य सरकार का मुख्य कार्यक्रम समेकित बाल विकास स्कीम है जो राज्य के 113 खण्डों में लागू है तथा इसको चालू वर्ष के अन्त तक राज्य के सभी 116 खण्डों में लागू कर दिया जायेगा ताकि राज्य की ग्रामीण जनता को शत-प्रतिशत इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

117. वर्ष 1996-97 के दौरान, 11.77 लाख लाभार्थियों, जिनमें 9.54 लाख बच्चे और 2.23 लाख गर्भवती औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें शामिल हैं, की पोषण सम्बन्धी जरूरतों पर 22.38 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। अपनी बेटी अपना धन नामक स्कीम चालू वर्ष के दौरान जारी रखी गई तथा वर्ष 1997-98 में इस स्कीम के अन्तर्गत 60,000 लाभार्थियों को अनुदान देने का प्रस्ताव है। महिला समृद्धि योजना जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान 9.87 लाख खाते खोलने की सम्भावना है, को आगामी वर्ष में भी जारी रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की शत-प्रतिशत बाह्य सहायता से एकीकृत महिला एम्पावरमैंट एवं विकास परियोजना ने महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिलों के 70 गांवों में प्रारम्भ होने के दूसरे वर्ष में ही महिला उत्थान के कई प्रभावशाली कार्य किये हैं।

12.00 बजे 118. वर्तमान सरकार के विशेष प्रयत्नों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी आगामी 5 वर्षों में सोनीपत, भिवानी और जीन्द, जिलों को हरियाणा, ग्रामीण महिला विकास तथा एम्पावरमेंट परियोजना के अन्तर्गत लाने के लिये 19.02 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था के लिये सहमत हो गए हैं।

119. हरियाणा समेकित महिला एम्पावरमेंट तथा विकास परियोजना गुड़गांव जिले के उपखण्डों सोहना, नूह तथा फारुख नगर में भी चलाई जानी है जिसके लिए फैडेरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से 700.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की जायेगी।

[श्री चरण दास]

120. राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को समाज सेवा देने के लिए वचनबद्ध है। समाज के इस वर्ग के लिये विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें चलाने हेतु वर्ष 1997-98 में 122.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

121. विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति परिवारों को सीधे लाभ देने वाली स्कीमों पर वर्ष 1996-97 के दौरान कुल योजना खर्च का 12.4 प्रतिशत व्यय किया गया है। 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1996 तक अनुसूचित जातियों के कुल 40698 परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने वर्ष 1997-98 में 14500 अनुसूचित जाति के परिवारों को 35.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना तैयार की है।

122. राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा सेना में कार्यरत सैनिकों की राष्ट्र के प्रति सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनेक सुविधाएं दी हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों पर 10.63 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

राजस्व विभाग

123. राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिवाड़ी जिले में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की एक मुख्य परियोजना शुरू की गई है। इस योजना से किसान बिना किसी असुविधा के सम्बन्धित कम्प्यूटर अनुभाग से मूल राजस्व अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे। अम्बाला, गुड़गांव, सिरसा और रोहतक ज़िलों में भी कम्प्यूटर लगाए गए हैं। शेष 12 ज़िलों को भी कम्प्यूटरीकरण स्कीम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ 15 लाख रुपये प्रति ज़िला के हिसाब से 1.80 करोड़ की राशि दे दी गई है।

124. किसानों को अपनी ज़मीन के अभिलेख की प्रतियों को प्राप्त करने और अपनी जमीन की मल्कियत की वास्तविक स्थिति से अवगत होने के लिए पटवारियों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के 17 ज़िलों की 17 तहसीलों में किसान पास बुक जारी करने की योजना पर कार्य चल रहा है। किसान पास बुकों की छपाई के लिए वर्ष 1997-98 में 2 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

125. चालू वर्ष के दौरान 15,000 एकड़ से अधिक भूमि की चकबन्दी का काम पूरा किया जा रहा है। इस काम में तेजी लाने के लिए वर्ष 1997-98 में 20,000 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र की चकबन्दी का काम पूरा किये जाने की आशा है और इस पर कुल 29 लाख रुपये की राशि खर्च होगी।

आपदा राहत

126. माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1995 के दौरान हरियाणा को अभूतपूर्व बाढ़ों का सामना करना पड़ा। राज्य के इतिहास में ऐसी बाढ़ें पहले कभी नहीं आई। वर्ष 1995 की बाढ़ों की याद अभी भूली नहीं थी कि 23 जून, 1996 और 24 जून, 1996 को हरियाणा के दक्षिणी-पश्चिमी भागों में भारी वर्षा हुई और 25 जून, 1996 को हथीन में मूसलाधार वर्षा हुई। राजस्थान से लगभग 25,000 क्यूसेक बाढ़ जल आ जाने से स्थिति और भी गम्भीर हो गई। राजस्थान की बाढ़ का पानी साहिबी नदी से होता हुआ रिवाड़ी और पटौदी के क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के जल का मेवात के 347 गांवों और आस-पास के क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और 5703 एकड़ क्षेत्र में फसलों को हानि पहुंची तथा 12314

मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ से 19 मनुष्यों की अमूल्य जाने गईं और 544 पशु मरे। राज्य सरकार ने तुरन्त बचाव और राहत कार्य शुरू किये। बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, राहत शिविरों में उन्हें भोजन, पेय जल, दवाइयां, दूध, मिट्टी का तेल और अन्य अनिवार्य वस्तुयें मुहैया करवाई गईं। सेना, एन०एस०जी० व एच०ए०पी० की सहायता ली गई। लोगों और राहत सामग्री को लाने, ले जाने के लिए मोटर बोटें लगाई गईं। चिकित्सा सुविधाएं देने तथा महामारी रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 37 चिकित्सा दल और 159 पैरा मैडिकल दलों को लगाया गया। चालू वर्ष में राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 95 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की गई। बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 1997-98 में 12.10 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98 में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत 26.44 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को रियायतें

127. हमारी सरकार यह स्वीकार करती है कि राज्य के विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने कर्मचारियों को अपने सीमित साधनों से बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए चालू वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को अनेक रियायतें दी गई हैं। चालू वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी, 1996 और जुलाई, 1996 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दो किश्तें दी गई हैं, जिन पर 108.49 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। केन्द्रीय सरकार की पद्धति पर अन्तरिम राहत देने पर 54.71 करोड़ रुपये, वर्ष 1994-95 से सम्बन्धित बोनस देने पर 42 करोड़ रुपये तथा 1-4-95 से ग्रेच्यूटी की राशि बढ़ाने के कारण 16 करोड़ रुपये खर्च हुए। निश्चित चिकित्सा भत्ता भी 60 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। मकान भत्ते में भी 25 रुपये की वृद्धि की गई है। वर्दी और वाशिंग भत्ता 60 रुपये से 75 रुपये मासिक कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण करने, वाहन खरीदने इत्यादि के लिए ऋण की सुविधा पूर्ववत् दी जाती रहेगी। जिस के लिए चालू वर्ष में 31.95 करोड़ रुपये तथा अगले वर्ष के लिए 35.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

128. माननीय सदस्य इस बात से अवगत ही हैं कि पांचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और भारत सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है। मेरी सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार की पद्धति पर लागू करने के लिए वचनबद्ध है।

संशोधित अनुमान 1996-97

129. पिछली सरकार ने चालू वर्ष का 33.67 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट प्रस्तुत किया था। उसमें वर्ष के दौरान बजट घाटे की सही स्थिति नहीं दर्शाई गई थी। पिछली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये घोषित कुछ लाभों के कारण 125 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च को उस वर्ष के बजट घाटे में नहीं दिखाया था। इसी प्रकार से बाढ़ के लिए केन्द्र से लिये कर्ज़ के कारण 139 करोड़ रुपये की अदायगी को केवल 48 करोड़ रुपये तक ही दिखाया गया। मई, 1996 में सत्ता में आने के बाद पता चला कि चालू वर्ष का बजट घाटा, पिछली सरकार द्वारा दर्शाये गये 33.67 करोड़ रुपये के घाटे की बजाए, 249.67 करोड़ रुपये का था।

130. अब, 1996-97 के संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष 4.59 करोड़ रुपये के सरप्लस से आरम्भ होकर 27.06 रुपये के घाटे से समाप्त होने की सम्भावना है।

[श्री धरण दास]

131. मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहूंगा कि आय साधनों की कमी को पूरा करने के लिये हमारी सरकार को आय बढ़ाने व खर्च में कमी करने के उपायों बारे कठोर निर्णय लेने पड़े। मई, 1996 में स्थापित संसाधन एवं मितव्ययिता समिति की सिफारिशों पर चालू वर्ष के दौरान लगभग 340 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आय साधन जुटाये गये। इसके अतिरिक्त, अन्य प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये। स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में 65 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी होने की सम्भावना हैं क्योंकि बजट अनुमानों में 225 करोड़ रुपये से बढ़ कर यह आय संशोधित अनुमान 1996-97 में 290 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। केन्द्रीय करों में भी राज्य के हिस्से में 14.82 करोड़ रुपये का इज़ाफा होने की सम्भावना है।

132. मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी के निष्ठापूर्वक प्रयत्नों के कारण भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान भूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 19.08 करोड़ रुपये, त्वरित सिंचाई लाभ स्कीम के लिए 45 करोड़ रुपये तथा शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए 3.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की है। नाबार्ड ने भी विभिन्न सिंचाई स्कीमों के लिए 58.66 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता दी है।

133. किफायती कदम उठाकर तथा योजनेतर खर्च को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये हैं। सभी योजना तथा योजनेतर स्कीमों की समीक्षा की गई है और ऐसी अनावश्यक स्कीमों, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, को बन्द कर दिया गया है। खर्च में कमी करने के विभिन्न उपायों को लागू किया गया ताकि गैर विकास खर्च की बढ़ौतरी को और कम किया जा सके। राज्य के उचित वित्तीय प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दिया गया। राजस्व खर्च पर कड़ा नियन्त्रण रखा गया है और केवल उन्हीं खर्चों की स्वीकृति दी गई जो आवश्यक तथा अपरिहार्य था।

134. हरियाणा के वित्तीय प्रबन्ध की गणना देश के सर्वोत्तम वित्तीय प्रबन्धों में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय में राज्य चौथे नम्बर पर है। हरियाणा ऐसे राज्यों में से एक है जिसका वर्तमान राजस्व का बकाया सरप्लस है। चालू वर्ष में हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) के अनुपात में वित्तीय घाटा 3.2 प्रतिशत होने की सम्भावना है जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। 31 मार्च, 1997 को हमारी ऋण-देयता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.9 प्रतिशत होनी सम्भावित है जबकि सभी राज्यों की औसत 30 प्रतिशत से ऊपर है। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य का योजनेतर राजस्व खर्च, कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 84 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है जबकि अधिकांश राज्यों में यह 100 प्रतिशत से भी अधिक है। वर्ष 1996-97 के दौरान योजनेतर राजस्व खर्च, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 12.4 प्रतिशत होने की सम्भावना हैं। राज्य का वेतन भुगतान कुल राजस्व खर्च का लगभग 47 प्रतिशत है जबकि अधिकांश राज्यों में यह 50 प्रतिशत से भी अधिक है। संशोधित अनुमान 1996-97 में, नशाबन्दी के कारण आर्थिक समस्याओं के बावजूद हरियाणा का वर्तमान राजस्व बकाया 215.17 करोड़ रुपये सरप्लस होने की सम्भावना है।

बजट अनुमान 1997-98

135. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन में वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों और 1997-98 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति दर्शायी गई है :-

बजट अनुमान 1997-98

(रुपये, करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1995-96	लेखे 1995-96	बजट अनुमान 1996-97	संशोधित अनुमान 1996-97	बजट अनुमान 1997-98
1	2	3	4	5	6
I. अर्थ शेष					
(क) महालेखाकार के अनुसार	(-)36.94	(-)36.94	22.82	4.69	(-)26.96
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(-)38.96	(-)38.96	20.80	4.59	(-)27.06
(ग) खजाना बिलों में निवेश	144.96	144.96	144.96	74.71	74.71
II. राजस्व लेखा					
प्राप्तियां	5022.55	5014.73	4823.23	6215.19	7442.57
खर्च	5448.88	5361.56	4976.40	6882.75	8156.03
अधिशेष/घाटा	(-)426.33	(-)346.83	(-)153.17	(-)667.56	(-)713.46
वर्तमान राजस्व बकाया (निवल)					
(क) राजस्व प्राप्तियां (प्लान ग्रांट एवं कोन्ट्रा एनट्रीज का निवल)	-	3227.99	3351.65	3380.10	3819.87
(ख) नॉन-प्लान राजस्व खर्च (निवल)	-	2743.77	3055.58	3164.93	3813.44
(बी०सी०आर० (क-ख)	-	(+)484.22	(+)296.07	(+)215.17	(+)6.43
III. पूंजीगत खर्च	324.91	285.87	466.54	442.65	638.68
IV. लोक ऋण					
लिया गया ऋण	1216.80	1072.08	1334.68	1375.19	1842.12
वापसी अदायगी	315.17	248.46	633.59	608.07	951.56
निवल	901.63	823.62	701.09	767.12	890.56
V. कर्जे और पेशगियां					
पेशगियां	389.17	382.07	398.89	382.18	371.74
वसूलियां	23.43	28.81	24.35	454.42	33.65
निवल	(-)365.74	(-)353.26	(-)374.54	(+)72.24	(-)338.09
VI. लघु बचतें भविष्य निधि आदि (निवल)	281.32	221.67	247.63	243.11	620.74
VII. जमा तथा पेशगियां, आरक्षित निधि और उचन्त तथा विविध (निवल)	(-)6.21	(-)12.32	(-)8.94	(-)3.91	(+)158.40
VIII. प्रेषण (निवल)	-	(-)5.38	-	-	-
IX. वर्ष के लेखे पर निवल	(+)59.76	(+)41.63	(-)54.47	(-)31.65	(-)20.53
X. वर्ष का इतिशेष					
(क) महालेखाकार के अनुसार	22.82	4.69	(-)31.65	(-)26.96	(-)47.49
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	20.80	4.59	(-)33.67	(-)27.06	(-)47.59
(ग) खजाना बिलों में निवेश	144.96	74.71	144.96	74.71	4.71

[श्री चरण दास]

136. वर्ष 1997-98 भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों के अनुसार 27.06 करोड़ रुपये के घाटे से शुरू व 47.59 करोड़ रुपये के घाटे से खत्म होने की संभावना है। अतः वर्ष के खाते में, वर्ष 1997-98 में 20.53 करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों में 31.65 करोड़ रुपये का घाटा है। वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों के अनुसार, वर्तमान राजस्व बकाये में, योजना संसाधनों पर भारी दबाव के बावजूद, 6.43 करोड़ रुपये का सरप्लस होने की सम्भावना है। बजट अनुमानों में राज्य योजनागत खर्च 1575 करोड़ रुपये तथा केन्द्र चालित और अन्य स्कीमों के लिये 246.25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

137. कर राजस्व में वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों की तुलना में, बजट अनुमान 1997-98 में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि प्रत्याशित है। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गए संकेतों के अनुसार रखा गया है। टैक्स तथा नॉन-टैक्स राजस्व प्राप्तियों के अनुमान प्रवृत्ति के आधार पर लगाये गये हैं और विभिन्न प्राप्तियों के लिये विभिन्न मापदण्ड अपनाये गये हैं। राज्य सरकार की आबकारी नीति के अनुसार, शराबबन्दी लागू करने की वजह से, वर्ष 1997-98 में उत्पाद राजस्व से कोई आमदन नहीं होगी। अर्थ-व्यवस्था में निहित लचीलेपन और प्रत्याशित बढ़ौतरी से राजस्व में और वृद्धि होना सम्भावित है। करों की चोरी व करों के ढांचे को तर्कसंगत बनाने से राज्य करों की वसूलियों में वृद्धि की आशा है।

138. मैं इस गरिमामयी सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 1997-98 में कुल कर राजस्व प्राप्तियों का 47.16 प्रतिशत कर राजस्व से प्राप्त होगा जबकि वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में यह 43.27 प्रतिशत था। नॉन-टैक्स प्राप्तियों का अंशदान वर्ष 1997-98 में 23.48 प्रतिशत होगा जबकि वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों में यह 23.03 प्रतिशत था। इस से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न किए।

139. हमारे सार्वजनिक उपक्रमों को भी राज्य योजना स्कीमों के लिये धन जुटाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। वर्ष 1997-98 के दौरान हमें अपने उपक्रमों से 80 करोड़ रुपये के अंशदान की आशा है।

140. हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिये भरसक प्रयास कर रही है। फलस्वरूप, हमें उम्मीद है कि हमारे कर्मचारी अपने भविष्य निधि खातों में वर्ष 1997-98 में 45 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त रूप में जमा करायेंगे। वर्ष, 1997-98 में 70 करोड़ रुपये तक के खज़ाना बिलों का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

141. योजनेतर खर्च का अनुमान लगाने में प्रायः योजना आयोग के अनुदेशों और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। योजनेतर खर्च को बढ़ने से रोकने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न देयता, जनवरी 1997 की देय होने वाली मंहगाई भत्ते की किश्त और वर्ष 1995-96 के लिए सरकारी कर्मचारियों को बोनस अदायगी हेतु, 628.60 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। बजट अनुमानों में 104.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था आठवीं योजना में चली उन योजना स्कीमों की देखरेख के लिये की गई है जिनको वर्ष 1997-98 से नॉन-प्लान साईड पर ले लिया गया है।

142. वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य द्वारा 1842.12 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण लिया जायेगा, जिसमें 177.41 करोड़ रुपये के बाज़ार ऋण शामिल हैं। 951.56 करोड़

रुपये के भुगतान के पश्चात् नेट सार्वजनिक ऋण 890.56 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा। 1996-97 के संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष में राज्य की कुल सार्वजनिक ऋण देयता में 767.12 करोड़ रुपये की वृद्धि होनी सम्भावित है। महालेखाकार हरियाणा के लेखों के अनुसार 31 मार्च, 1996 को राज्य की कुल ऋण देयता, 6025.51 करोड़ रुपये से 16.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर 31 मार्च, 1997 तक 7026.15 करोड़ रुपये हो जायेगी और फिर 22.2 प्रतिशत की दर से बढ़कर 31 मार्च, 1998 को 8586.48 करोड़ रुपये होनी सम्भावित है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में राज्य की कुल ऋण देयता वर्ष 1996-97 के दौरान 21.9 प्रतिशत, और वर्ष 1997-98 में 23.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

143. राज्य की ब्याज देयता 23.3 प्रतिशत की दर से वर्ष 1996-97 के संशोधित अनुमानों में 730.86 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 के बजट अनुमानों में 901.48 करोड़ रुपये होनी अनुमानित है। यह देयता पूंजी निर्माण में बढ़ौतरी हेतु अधिक ऋण लेने के कारण से है।

144. माननीय सदस्य यह मानेंगे कि बजट में घाटा कम से कम रखा गया है और यह उपयुक्त सीमा के अन्दर है। मौजूदा साधनों से बेहतर वसूली करके, राज्य व केन्द्रीय करों में सामान्य लचीलेपन, तथा करों की चोरी को रोककर और योजनेतर खर्च पर कड़ा नियन्त्रण रखकर, इस घाटे को पूरा किया जायेगा।

145. अब मैं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में स्थानीय बिक्री कर में राहत देने बारे प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं। सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर टायर पर बिक्री कर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं जिससे किसानों को राहत मिलेगी। लोगों की धार्मिक भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए धूप व अगरबत्ती को बिक्री कर से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं जिस पर वर्तमान बिक्री कर की दर 10 प्रतिशत है गरीब रिक्शा चालकों को राहत देने के उद्देश्य से साईकिल रिक्शा पर बिक्री कर में पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं। साइकिल रिक्शा पर वर्तमान बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत है। अन्त में मैं हस्त निर्मित कागज़ जिसका उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से उचित ढंग से होता है, को भी बिक्री कर से पूरी छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं।

146. हमारी सरकार ने सदैव हरियाणा के लोगों की ईमानदारी, मेहनत व कर्त्तव्य परायणता से सेवा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना में सभी विकास कार्यक्रमों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये मैं सभी माननीय सदस्यों तथा हरियाणा की जनता से सहयोग और सहायता की अपेक्षा करता हूँ।

महोदय, अब मैं बजट अनुमान 1997-98 इस गरिमामय सदन में विचार तथा अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द।

*12.25 hrs. Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow. (The Sabha than *adjourned till 9.30 a.m. on thursday the 13th March, 1997.)

28806—HVS—H.G.P. Chd.